साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 10 अगस्त से 16 अगस्त 2026
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 03
बृजमोहन के समर्थन में सामने आई एमपी की सांसद

पेज 08
पहली बार बस्तर के 92 गांवों में लहराएगा तिरंगा

वर्ष : 02 अंक : 23 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 05 परिसीमन से क्यों चिंतित हैं दक्षिणी राज्य ?

सुशासन और औद्योगिक क्रांति का नया सवेरा

कैबिनेट के 7 बड़े फैसलों से बदलेगी छत्तीसगढ़ की तस्वीर

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

छत्तीसगढ़ को तकनीक-संपन्न, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में कई युगांतरकारी निर्णय लिए गए। यह ऐतिहासिक कदम राज्य में सुशासन, औद्योगिक निवेश, वित्तीय अनुशासन और बुनियादी ढांचे के चौमुखी विकास का मजबूत रोडमैप हैं।राज्य में सुशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने ₹500 करोड़ के बजट से 'छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन' (5 वर्ष) की शुरुआत होगी। इसके तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 300+ स्टार्टअप्स को सहायता और 7.5 लाख लोगों को AI प्रशिक्षण मिलेगा।औद्योगिक क्षेत्र में मिनीरत्न उपक्रम BEML को हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट संयंत्र हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। यह राज्य का पहला भारी मशीन निर्माण उद्योग होगा, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार सृजित होंगे।पारदर्शिता के लिए PWD में WAMIS डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू होगा, वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के नियमों में ढील देकर ग्रामीण सड़कों का विस्तार आसान किया जाएगा।

तकनीक और कौशल: ₹500 करोड़ से 'छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन' को हरी झंडी

राज्य को डिजिटल अर्थव्यवस्था और सुशासन में अग्रणी बनाने के लिए 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट से 'छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन' शुरू करने को मंजूरी दी गई है। यह भारत सरकार के IndiaAI Mission के अनुरूप है।

100 AI डेटा लैब तथा 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को वित्तीय व तकनीकी सहायता मिलेगी।6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशासनिक कार्यों को तीव्र और सुगम बनाने हेतु 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।

औद्योगिकीकरण: BEML संयंत्र की स्थापना से भारी मशीन निर्माण क्षेत्र में नई क्रांति

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित मिनीरत्न उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को 'हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट मैन्युफैक्चरिंग' (Heavy Earth Moving Equipment) संयंत्र के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन का फैसला हुआ है।

यह छत्तीसगढ़ का पहला भारी मशीन निर्माण उद्योग होगा, जो राज्य को देश के औद्योगिक मानचित्र पर नया मुकाम देगा। भारी निवेश आकर्षित होगा और स्थानीय युवाओं के लिए व्यापक रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। राज्य के MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम) उद्योगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत बैकबोन मिलेगा।

निर्माण कार्यों में पारदर्शिता: PWD में लागू होगा WAMIS डिजिटल प्लेटफॉर्म

लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यों में पारदर्शिता और गतिशीलता लाने के लिए वर्क्स एण्ड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) के प्रथम चरण को मंजूरी दी गई है। इसे सी-डैक (C-DAC), पुणे द्वारा तैयार किया गया है।

एकीकृत डिजिटल सुविधाएं: प्रशासनिक स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक (e-MB), बिल भुगतान और गुणवत्ता ट्रैकिंग सब एक प्लेटफॉर्म पर होगा। कार्यों में देरी कम होगी और भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी एवं तेज होगी। PWD के सफल क्रियान्वयन के बाद इसे अन्य निर्माण विभागों में विस्तारित किया जाएगा।

ग्रामीण विकास: 'मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना' में बड़े संशोधन

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए योजना के दिशा-निर्देशों में सुधार किया गया है। ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क/नाली निर्माण और पूर्व में मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। वे सभी ग्रामीण मार्ग जो PMGSY या अन्य योजनाओं में शामिल नहीं हैं, वे अब इस योजना के पात्र होंगे। नाबार्ड ऋण, खनिज न्यास मद (DMFT), और अधोसंरचना विकास मद जैसे स्रोतों का उपयोग किया जा सकेगा। कार्यों की समीक्षा और विभागों में समन्वय के लिए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा।

वैश्विक साझेदारी: ADB से मिला ₹15 करोड़ का पूर्णतः अनुदान

'छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047' के क्रियान्वयन को गति देने के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) से 15 करोड़ रुपये का 100% अनुदान प्राप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। 1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029 तक (3 वर्ष)। इसमें राज्य या केंद्र सरकार का कोई वित्तीय अंशदान नहीं होगा। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में सुधार, PPP मॉडल को बढ़ावा, ग्रीन फाइनेंसिंग, SOEs की क्षमता में वृद्धि और क्लाइमेट-रेजिलिएंट विकास परियोजनाओं के लिए PMU स्थापित करना।

लागू होगा State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल

सरकारी फंड का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य की योजनाओं में भी केंद्र की तर्ज पर S-SNA मॉडल लागू किया जाएगा। अब योजना की राशि विभिन्न बैंक खातों में बेकार नहीं पड़ी रहेगी; आवश्यकता पड़ने पर सीधे वेंडर या हितग्राही के खाते में ट्रांसफर (DBT) होगी। गबन, निष्क्रिय राशि और बैंकिंग फ्रॉड की संभावना पूरी तरह खत्म होगी। राज्य की नकदी प्रबंधन क्षमता मजबूत होगी और अनावश्यक ब्याज का बोझ घटेगा।

CSPGCL जारी करेगा ₹200 करोड़ के NCDs/बॉन्ड

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) में आम और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ₹200 करोड़ तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार मूलधन व ब्याज भुगतान पर गारंटी प्रदान करेगी और प्रत्याभूति शुल्क में छूट देगी। इससे प्राप्त वित्तीय संसाधनों का उपयोग राज्य की बिजली आपूर्ति और बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने में होगा।

कचरे और पैरे से बनेगी ग्रीन गैस

छत्तीसगढ़ में कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब धान के पैरे, गोबर और शहरी गीले कचरे से स्वच्छ ईंधन (ग्रीन एनर्जी) तैयार किया जाएगा। राज्य में हर साल निकलने वाले करीब 150 लाख टन पैरे, 18 लाख टन से ज्यादा गोबर और 6 लाख टन से अधिक घरेलू जैविक कचरे के जरिए सालाना 10 लाख टन से अधिक कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) उत्पादन की संभावना है। राज्य सरकार ने कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) नीति-2026 के तहत शुरुआती चरण में 5 लाख टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा में 8 सीबीजी प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं का विकास BPCL (भारत पेट्रोलियम) और गेल इंडिया लिमिटेड (GAIL) के सहयोग से किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में आठ सीबीजी प्लांट स्वीकृत हो चुके हैं और भूमि आवंटन जारी है। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण यहां फसल अवशेष, गोबर और गीले कचरे की पर्याप्त उपलब्धता है, जिनका उपयोग सीबीजी प्लांट में कर पर्यावरण को सुरक्षित किया जाएगा।

कचरा प्रबंधन और किसानों की अतिरिक्त आय

खरीफ सीजन में धान की फसल के बाद बड़े पैमाने पर पैरा निकलता है। पशु चारे के बाद बचा हुआ पैरा अक्सर खेतों में जला दिया जाता है। अब यही पैरा सीबीजी संयंत्रों के लिए मुख्य कच्चा माल बनेगा, जिससे किसानों को इसे बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

नगरीय कचरे का उपयोग: प्रदेश के नगरीय निकायों से प्रतिदिन निकलने वाले लगभग 1650 टन ठोस कचरे (अकेले रायपुर में 550 टन/दिन) का उपयोग बायोगैस बनाने में होगा। इससे निकायों पर कचरा निपटान का दबाव कम होगा।

निवेशकों के लिए विशेष पैकेज

राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूमि डायवर्जन शुल्क, पंजीयन शुल्क और बिजली शुल्क में विशेष रियायतें दी हैं। साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाली इकाइयों को कर्मचारियों के वेतन और EPF अंशदान में सरकारी प्रतिपूर्ति (रिफंड) मिलेगी।

सीबीजी नीति-2026 की मुख्य बातें

पात्रता: केंद्र की SATAT योजना से स्वीकृत कंपनियां और GOBARdhan पोर्टल पर पंजीकृत डेवलपर इसके पात्र होंगे।

पुराने प्लांट शामिल: पूर्व से संचालित पात्र सीबीजी संयंत्रों को भी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ मिलेगा।

कच्चे माल का आवंटन: हर जिले को कैचमेंट एरिया बनाया जाएगा, जिसमें किसी एक डेवलपर को जिले की 80% से अधिक क्षमता आवंटित नहीं की जाएगी।

शुल्क में राहत: भूमि डायवर्जन, पंजीयन शुल्क और बिजली कनेक्शन पर छूट मिलेगी।

रोजगार प्रोत्साहन: स्थानीय कर्मचारियों के वेतन और ईपीएफ (EPF) अंशदान पर वित्तीय सहायता।

जैविक खाद की बिक्री: सीबीजी निर्माण के दौरान उप-उत्पाद के रूप में मिलने वाली जैविक खाद की मार्केटिंग सहकारी समितियों, कृषि, वन और उद्यानिकी विभागों द्वारा की जाएगी।

समयावधि व निगरानी: यह नीति 2030 तक लागू रहेगी। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (CBDA) इसकी नोडल एजेंसी होगी और राज्य स्तरीय SATAT समिति इसकी निगरानी करेगी।

घटारानी वाटरफॉल में हादसा, पैर फिसलने से नीचे गिरा युवक

रायपुर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल घटारानी वाटरफॉल में घूमने पहुंचे एक युवक के साथ हादसा हो गया। झरने के पास अचानक पैर फिसलने से युवक ऊंचाई से नीचे जा गिरा। हादसे के बाद युवक बेहोशी की हालत में था। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मदद करते हुए पुलिस और आपातकालीन सेवा को सूचना दी, जिसके बाद घायल युवक को 112 की मदद से फिंगेश्वर के शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए वाटरफॉल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पर्यटकों और आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक को संभाला और उसे सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। प्राथमिक जानकारी के अनुसार युवक को हादसे में गंभीर चोटें आई हैं।

जानकारी के मुताबिक, धमतरी जिले के रावा निवासी खूबलाल डिमर घटारानी वाटरफॉल घूमने पहुंचे थे। इसी दौरान झरने के आसपास मौजूद ऊंचाई वाले हिस्से में अचानक उनका पैर फिसल गया। पैर फिसलते ही युवक अपना संतुलन खो बैठा और ऊंचाई से नीचे जा गिरा। गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आईं और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। हादसा देखकर वहां मौजूद अन्य पर्यटक भी घबरा गए और तत्काल युवक की मदद के लिए आगे आए।

112 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और आपातकालीन सेवा को सूचना दी। इसके बाद 112 की टीम की मदद से घायल युवक को फिंगेश्वर के शासकीय अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में युवक का उपचार शुरू किया गया। हादसे में उसे गंभीर चोटें आने की बात सामने आई है।

असम के बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार देगी 5 करोड़

रायपुर। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता और राहत-पुनर्वास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। सीएम साय ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से फोन पर बात कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और कहा कि संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ पूरी एकजुटता के साथ असम के भाई-बहनों के साथ खड़ा है।

मुख्यमंत्री साय ने असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। यह राशि राहत एवं पुनर्वास से जुड़े कार्यों में उपयोग की जाएगी। सरकार की ओर से दी जाने वाली यह सहायता असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने और आपदा के बाद जरूरी पुनर्वास कार्यों में सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से दूरभाष पर चर्चा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से दूरभाष पर चर्चा कर राज्य में बाढ़ की स्थिति और प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी ली। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री साय ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में छत्तीसगढ़ की जनता असम के अपने भाई-बहनों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ के लोग असम के अपने भाई-बहनों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि मुश्किल समय में एक-दूसरे की सहायता करना देश की एकजुटता और सहयोग की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने असम में राहत कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग की भावना व्यक्त की।

खरौद में AI ने मचाई खलबली, तालाब में मगरमच्छ की फर्जी तस्वीर वायरल

खरौद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में तकनीक जहां पढ़ाई, कारोबार और मनोरंजन को आसान बना रही है, वहीं इसका गलत इस्तेमाल कभी-कभी लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी कर सकता है। जांजगीर-चांपा जिले के खरौद में ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां AI से तैयार की गई मगरमच्छ की तस्वीर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। तालाब में मगरमच्छ दिखाई देने की खबर के बाद ग्रामीणों में ऐसा डर बैठा कि करीब तीन दिन तक तालाब के आसपास निगरानी और पहरा चलता रहा। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची और तालाब में मगरमच्छ होने की आशंका को लेकर जांच-पड़ताल की गई। लेकिन जब पूरे मामले की सच्चाई सामने आई तो ग्रामीण भी हैरान रह गए। जिस मगरमच्छ को लेकर पूरा इलाका खौफ में था, वह असली नहीं, बल्कि AI से तैयार की गई तस्वीर थी। जानकारी के अनुसार, खरौद क्षेत्र में एक तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची। तस्वीर में तालाब के पानी के बीच एक बड़ा मगरमच्छ दिखाई दे रहा था। तस्वीर को देखकर पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि तालाब में वास्तव में मगरमच्छ मौजूद है। तस्वीर तेजी से लोगों के बीच शेयर होने लगी। देखते ही देखते तालाब में मगरमच्छ होने की खबर पूरे इलाके में फैल गई। ग्रामीणों ने एहतियात के तौर पर तालाब के आसपास जाना कम कर दिया। तालाब में नहाने और अन्य कामों के लिए जाने वाले लोग भी सतर्क हो गए।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर दो जजों का ट्रांसफर

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ओड़िशा हाईकोर्ट के दो जजों के तबादले की अनुशंसा की है। कॉलेजियम की 6 अगस्त 2026 को हुई बैठक में दोनों न्यायाधीशों के स्थानांतरण का फैसला लिया गया। इसके तहत जस्टिस मानस रंजन पाठक को ओड़िशा हाईकोर्ट से गुजरात हाईकोर्ट और जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा को ओड़िशा हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने की अनुशंसा की गई है। कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिहाज से यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा के आने से हाईकोर्ट को एक अतिरिक्त न्यायाधीश मिलेगा। जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट आने से न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट में लंबित मामलों और न्यायिक कार्यों के बीच एक नए जज की नियुक्ति से कामकाज में मदद मिल सकती है। कॉलेजियम ने जस्टिस मोहपात्रा के साथ जस्टिस मानस रंजन पाठक के तबादले की भी अनुशंसा की है। जस्टिस पाठक को गुजरात हाईकोर्ट भेजा जाएगा।

पावर प्लांट में हादसा, हाइवा की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत

रायपुर। रायपुर के पावर प्लांट परिसर में हाइवा की चपेट में आने से 26 वर्षीय कर्मचारी केशव कुमार महिलांगे की मौत हो गई। हादसे के बाद मुआवजे और शव सुपुर्दगी की मांग को लेकर परिजनों ने प्लांट के मुख्य गेट पर धरना शुरू कर दिया। उनके समर्थन में मजदूर यूनियन और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सदस्य भी मौके पर पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक पावर प्लांट परिसर में काम के दौरान केशव कुमार महिलांगे हाइवा की चपेट में आ गए। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद घायल कर्मचारी को बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। मृतक के परिजन प्लांट पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर विरोध शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि परिवार के सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने हादसे के बाद उचित मुआवजे की मांग की है।

मुख्य कमाऊ सदस्य के निधन पर बीपीएल परिवारों को मिलेगी 20 हजार रूपए की त्वरित वित्तीय राहत

मुसीबत में संबल बनी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

विष्णु प्रसाद वर्मा
सहायक संचालक, जनसंपर्क

शहर सत्ता/रायपुर। किसी भी परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य का अचानक चले जाना केवल एक अपूरणीय भावनात्मक क्षति ही नहीं होता, बल्कि उस पूरे घर की आर्थिक नींव को भी पूरी तरह हिलाकर रख देता है। ऐसे कठिन समय में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को तत्काल सहारा और आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन का समाज कल्याण विभाग 'राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना' का प्रभावी ढंग से संचालन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसी बीपीएल परिवार के मुख्य आजीविका प्रदाता सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित वारिस मुखिया को 20 हजार रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। संकट के क्षणों में दी जाने वाली यह राशि प्रभावित परिवार को तात्कालिक राहत पहुँचाने के साथ-साथ उन्हें पुनः संबल प्रदान करने में बेहद मददगार साबित होती है।

योजना की पात्रता हेतु मुख्य शर्तें

इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक मापदंड निर्धारित किए गए हैं। योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनका नाम वर्ष 2002 की बीपीएल सर्वे सूची में दर्ज है। इसके साथ ही सहायता राशि तभी स्वीकृत की जाती है जब मृत व्यक्ति की आय से ही परिवार की दैनिक आजीविका चलती रही हो। पात्रता के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि मृत्यु की तिथि को मृतक सदस्य की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया को बेहद सरल और सुलभ बनाया गया है। आवेदक को पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है, जिसमें मृत्यु के समय उनकी निर्धारित आयु स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो। इसके अतिरिक्त वर्ष 2002 का बीपीएल प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटो और छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।

जानकारी व सहायता हेतु संपर्क करें

नागरिकों की सुविधा के लिए आवेदन जमा करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी अपने आवेदन पत्र निकटतम लोक सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में जमा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों के निवासी अपने क्षेत्र की नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी, सवाल या सहायता के लिए विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 155326 तथा टोल-फ्री नंबर 1800-233-8989 भी जारी किए गए हैं।

कांग्रेस बोली ई-20 पेट्रोल की अनिवार्यता जनता को परेशान कर रही

शहर सत्ता/रायपुर। एथेनाल मिश्रित पेट्रोल (ई-20) के कारण जनता परेशान हो रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ई-20 पेट्रोल देश की जनता के लिए मुसीबत बना। सरकार ई-20 पेट्रोल को वैकल्पिक करे जिस उपभोक्ता को ई-20 पेट्रोल नहीं डलवाना हो उसे बिना एथेनाल मिश्रित पेट्रोल डलवाने की छूट मिलनी चाहिए। अभी पेट्रोल पंपों पर सिर्फ ई-20 पेट्रोल मिल रहा है, जिसके कारण जनता परेशान हो रही है। एथेनाल मिलाकर सरकार तो मुनाफा कमा रही है लेकिन जनता तो प्योर पेट्रोल की कीमत का भुगतान कर रही है तथा गाड़ी खराब होने की परेशानी अलग से भुगत रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार ने नफा नुकसान का वैज्ञानिक परीक्षण किये बिना पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनाल मिला कर पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया है जिसके कारण लोगों के वाहन खराब हो रहे है। ई-20 पेट्रोल के कारण लोगों की गाड़ियां न सिर्फ खराब हो रही है इस एथेनाल वाले पेट्रोल के कारण वाहनों की माईलेज भी आधा हो गया है। मोदी सरकार ने अपने एक मंत्री की जिद और उनके पुत्रों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश को संकट में डाल दिया है। ई-20 पेट्रोल आम पेट्रोल की अपेक्षा शुरू नहीं है इसीलिए माईलेज में कमी आ रही है तथा गाड़ियों के इंजन भी खराब हो रहे है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विशेषज्ञों का कहना है ई-20 पेट्रोल के कारण एथेनाल हवा से नमी को जल्दी सोख लेता है। पुराने वाहनों में लगे मेटल (लोहे) के फ्यूल टैंक और फ्यूल पंप में इस नमी के कारण अंदर ही अंदर जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है, जो इंजन में जाकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है।

BJYM बोली- 'न्यूज़' और 'हे-राम' पर भूपेश-बैज ने झूठ फैलाया

शहर सत्ता/रायपुर। CGPSC के SI रिजल्ट में 'न्यूज़' और 'हे राम' जैसे नामों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी बयानबाजी तक पहुंच गया है। भाजयुमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने अभ्यर्थियों के वीडियो और दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि बिना तथ्य युवाओं की मेहनत पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की सूबेदार, उप निरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के प्रीलिम्स रिजल्ट में कुछ अभ्यर्थियों के नाम चर्चा में आ गए। मेरिट लिस्ट में 'NEWS' और 'SPACE RANI' नाम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इनके नामों को लेकर सवाल उठने लगे। इसी बीच रायगढ़ के एक युवक ने वीडियो जारी कर खुद को 'NEWS' नाम का अभ्यर्थी बताया है। उसका पूरा नाम न्यूज कुमार प्रधान है। उसका कहना है कि 10वीं की मार्कशीट में सरनेम दर्ज नहीं हो पाया था। इसके बाद 12वीं, कॉलेज और आधार कार्ड समेत दूसरे दस्तावेजों में भी उसका नाम 'News' ही दर्ज होता चला गया। 'HE RAM' और 'TUFAIL' नाम के अभ्यर्थियों ने भी वीडियो के जरिए अपने नाम सही होने की बात कही है।

सांसद-आईएएस विवाद : बृजमोहन के समर्थन में सामने आई एमपी की सांसद

108 एंबुलेंस टेंडर की जांच और कार्रवाई की मांग, अग्रवाल से कहा था-जो करना है कर लो

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर से भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव IAS अमित कटारिया के बीच चल रहे विवाद में अब सांसद भी लामबंद होने लगे हैं। मध्यप्रदेश की मध्यप्रदेश की पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री जयश्री बनर्जी भी बृजमोहन मामले में सामने आई हैं। जयश्री बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजकर अमित कटारिया के खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

जयश्री बनर्जी ने 5 अगस्त 2026 को लोकसभा अध्यक्ष को यह पत्र भेजा है। जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से उन्हें रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की ओर से IAS अमित कटारिया के खिलाफ की गई शिकायत की जानकारी मिली। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में लोकसभा सचिवालय की ओर से तथ्यात्मक जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा जयश्री बनर्जी ने 108 एंबुलेंस टेंडर की जांच और कार्रवाई की मांग की है।

108 एंबुलेंस टेंडर में कथित गड़बड़ी का मुद्दा

पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी ने अपनी शिकायत में अमित कटारिया के स्वास्थ्य विभाग में कार्यकाल के दौरान 108 एंबुलेंस सेवा के टेंडर का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में कथित तौर पर नियमों की अनदेखी और अनियमितताओं के आरोपों की जांच कराने की मांग की है। जयश्री बनर्जी ने कहा कि 108 एंबुलेंस सेवा सीधे आम लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी है। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं। उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

लोकसभा अध्यक्ष से तीन मांगें

जयश्री बनर्जी ने पत्र में लोकसभा अध्यक्ष से सांसद बृजमोहन अग्रवाल की शिकायत का संज्ञान लेने, अमित कटारिया के खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने और जांच में अनियमितता या भ्रष्टाचार साबित होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और जनप्रतिनिधियों के सम्मान की रक्षा के लिए इस मामले में उचित कदम उठाना जरूरी है।

तलवार से काटा केक: वीडियो वायरल

- **छत्तीसगढ़ शिवसेना प्रमुख ने कहा, कार्यकर्ताओं के कहने पर ऐसा किया**

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ शिवसेना प्रमुख धनंजय परिहार का तलवार से केक काटने का वीडियो वायलर हो रहा है। घटना रायपुर के टिटोस क्लब की है। धनंजय परिहार टिटोस क्लब के मालिक भी हैं। आरोप है कि इसी क्लब में रात 12 बजे के बाद भी पार्टी चलती रही और शराब परोसी जा रही थी। मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लब के अंदर बड़ी संख्या में युवक-युवतियां मौजूद हैं। तेज म्यूजिक के बीच पार्टी चल रही है। इसी दौरान शिवसेना प्रमुख केक लेकर पहुंचते हैं और तलवार से केक काटते हैं। आसपास मौजूद लोग जश्न मनाते और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। वहीं, वायरल वीडियो को लेकर शिवसेना प्रमुख धनंजय परिहार ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह वीडियो करीब 6 महीने पुराना है। कार्यकर्ताओं के कहने पर उन्होंने तलवार से केक काटा था। उनका कहना है कि केक काटने का उद्देश्य किसी पर हमला करना नहीं था।

6 महीने पुराना वीडियो हुआ वायरल

बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने पहले शिवसेना प्रमुख धनंजय परिहार का जन्मदिन था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने टिटोस क्लब में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेशन के दौरान उन्होंने तलवार से केक काटा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आधी रात के बाद भी क्लब में युवक-युवतियां पार्टी करते नजर आ रहे हैं।

विश्व आदिवासी दिवस का विरोध कर भाजपा आदिवासी अस्मिता का विरोध कर रही - दीपक बैज

शहर सत्ता/रायपुर। भाजपा सरकार के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को शासकीय स्तर पर नहीं मनाये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा जिस प्रदेश की 32 प्रतिशत आबादी आदिवासियों की हो, जहां पर दुनिया की सबसे प्राचीन आदिवासी सभ्यता निवास करती हो वहां की सरकार यदि आदिवासी दिवस मनाने से परहेज कर रही है तो यह आदिवासी समाज का अपमान है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन आदिवासी सभ्यता और संस्कृति पर गौरव का दिन है। आदिवासी संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और मौलिक संस्कृति है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि दुनिया के सामने यह बताना कि आदिवासी समाज और उनकी सभ्यता किसी से कम नहीं यह दिन आदिवासी समाज के लिये गर्व का दिन है। प्रदेश का मुखिया आदिवासी समाज से आता है। उसके बाद प्रदेश में शासकीय तौर पर आदिवासी दिवस मनाने से परहेज किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज का दिन केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है। आज का दिन हमें अपनी जड़ों को याद करने का दिन है। आज का दिन उन महान परंपराओं को नमन करने का दिन है, जिन्होंने सदियों से जल, जंगल, जमीन, प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन बनाकर रखा है। हमारे आदिवासी समाज ने हमें सिखाया है कि जंगल केवल लकड़ी नहीं है, नदी केवल पानी नहीं है।

प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े, महिलाएं सुरक्षित नहीं: वंदना राजपूत

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों को भय मुक्त वातावरण देने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। विगत दो वर्ष भीतर ही प्रदेश में दुष्कर्म के 6191 प्रकरण दर्ज किए गए, अर्थात रोज 9 महिला या बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं, हर 3 घंटे में कोई ना कोई महिला रेप का शिकार होने मजबूर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। सबसे ज्यादा दुष्कर्म और चाकूबाजी राजधानी रायपुर में ही हो रही हैं, बिलासपुर और कोरबा दूसरे और तीसरे स्थान पर है। प वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा के प्रशासन में छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन औसतन 8 से 9 महिलाएं दुराचार के शिकार हो रही है, हर दूसरे दिन सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है, सरकारी आश्रम स्कूलों में नाबालिक बच्चियों गर्भवती हो रही है, जब पीड़िता थाने जाते हैं तो एफआईआर करके आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय पीड़ितों को ही प्रताड़ित किया जाता है।

फीस निर्धारण के नाम पर छात्रों से लूट बंद हो: संजय ठाकुर

छात्र आंदोलित हो गये तो छग को जंतर मंतर बनते देर नहीं लगेगी

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसियेशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रदेश के समस्त निजी वि. वि. द्वारा संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शुल्क का निर्धारण छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, रायपुर के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें।

ठाकुर ने बताया की इस संबंध में प्रवेश एवम फीस विनियामक समिति के पूर्व अध्यक्ष रिटायर्ड जज श्री प्रभात शास्त्री ने दिनांक 13 सितंबर 2024 को निजि विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को पत्र जारी कर बताया था कि छत्तीसगढ़ के सभी निजि विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है, कि वे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण संबंधित समिति से ही कराये तथा इस कार्यालय को आवश्यक रूप से अवगत कराये,इसके पश्चात छग के समस्त निजि वि.वि. को स्पष्ट आदेश छग निजी विश्व विद्यालय विनियामक आयोग, द्वारा दिनांक 23-6-2025 के पत्र के माध्यम से पहले ही दे चुका है, लेकिन शासन का भ्रष्ट तंत्र यह होने नहीं दे रहा। जब भी मांग उठती है ,शासन के साथ मार्गदर्शन लेने का खेल शुरु हो जाता है।

ठाकुर ने बताया की AFRC चेयरमैन द्वारा लिखा जा चुका है , कि फीस तय करना AFRC के अंतर्गत आता है। निजि विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सचिव ने सभी निजि विश्वविद्यालयो के कुलसचिवों को लिख दिया कि फीस AFRC से ही तय कराना है, और तो और तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने भी मंत्रालय को स्पष्ट प्रतिवेदन दे दिया है,कि फीस AFRC ही तय करेगी। अब इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात शासन को स्पष्ट चेतावनी के साथ दिशा निर्देश जारी कर भ्रष्ट गतिविधि पर रोक लगानी चाहिये। संजय ठाकुर ने बताया की सन् 2008 में केंद्र शासन के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति AFRC का गठन हुआ था जिसका मूल उद्देश्य राज्य के सभी निजी व शासकीय विश्वविद्यालय में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे - MBA,B.E, Pharmacy B.Tech ,B.Ed., M.Ed., M.C.A, B.P.Ed, M.P.Ed. B.Arch की फीस तय करना था। दुखद है की आज 18 साल भी यह लागू नहीं हो पा रहा है।

संजय ठाकुर ने कहा की एक लंबे समय से छात्र मांग करते आ रहे हैं कि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता एवं विधिसम्मत व्यवस्था सुनिश्चित की जाये लेकिन लाखों छात्रों से जुड़े इस विषय को प्रशासनिक प्रक्रिया में उलझाकर वर्षों से छात्रों का शोषण जारी है। अगर छात्र आंदोलित हो गये तो छग को जंतर मंतर बनते देर नहीं लगेगी।

नकटी के बाद अब चंदेरी की चरागाह जमीन उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी

पूर्व मंत्री अकबर ने सरकार पर उठाए सवाल

रायपुर। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा तहसील के ग्राम चंदेरी में चरागाह की जमीन को औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिए जाने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नकटी कांड के बाद अब चंदेरी की चरागाह भूमि को उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश और शासन के निर्देशों की भी अनदेखी की जा रही है।

पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री के पूर्व में दिए गए आश्वासन का भी हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी 2024 को दामाखेड़ा में कबीरपंथ के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के दायरे में उद्योग नहीं लगाने को लेकर आश्वासन दिया था। अकबर का आरोप है कि मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बावजूद चंदेरी में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए चरागाह की जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि यदि दामाखेड़ा के आसपास उद्योग नहीं लगाने का आश्वासन दिया गया था तो चंदेरी की भूमि को औद्योगिक प्रयोजन के लिए किस आधार पर दिया गया। अकबर के मुताबिक चंदेरी में करीब 23.93 हेक्टेयर यानी लगभग 59 एकड़ चरागाह भूमि को नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए उद्योग विभाग को आधिपत्य में दिया गया है। उनका कहना है कि यह जमीन केवल एक गांव के मवेशियों के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास की करीब 8 से 10 ग्राम पंचायतों के गोवंश और अन्य मवेशियों के लिए भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक चरागाह है।

मोहम्मद अकबर ने अपने आरोपों के समर्थन में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 10 मार्च 2011 के निर्देश का हवाला दिया। उनके अनुसार इस निर्देश में सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित भूमि को भविष्य में किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित नहीं किए जाने की बात कही गई है। अकबर का दावा है कि इसके बावजूद चंदेरी तहसील के खसरा नंबर 1660, 2206, 2207 और 1743 की कुल करीब 23.93 हेक्टेयर भूमि को उद्योग विभाग के आधिपत्य में दे दिया गया। अकबर ने दावा किया कि नायब तहसीलदार सिमगा की 19 जनवरी 2025 की आदेश-पत्रिका में ग्राम पंचायत चंदेरी की आपत्ति का उल्लेख किया गया था।

संपादकीय

सुकांत राजपूत

अब 'गढ़' नहीं 'सुघड़'

जनता प्रकृति की तरह होती है। वह हर बार प्रलय नहीं लाती, पहले संकेत देती है। कभी मतदान प्रतिशत घटता है, कभी मतों का अंतर कम होता है, कभी परंपरागत मतदाता घर बैठ जाता है। जो इन संकेतों को समझ लेते हैं, वे स्वयं को सुधार लेते हैं। जो इन्हें अहंकार में अनदेखा करते हैं, उनके लिए चुनाव परिणाम कठोर संदेश बनकर सामने आते हैं। क्योंकि राजनीति में अब 'गढ़' नहीं 'सुघड़' चुनने का वक्त है। लोकतंत्र में कोई भी सीट स्थायी गढ़ नहीं होती। जनता किसी दल की बंधक नहीं होती। वह सम्मान देती है, लेकिन समय आने पर जवाब भी देती है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ा मंत्र यही होना चाहिए—कार्यकर्ता का सम्मान, समाज से सतत संवाद, टिकट वितरण में पारदर्शिता और जनता के विश्वास को कभी स्वाभाविक मान लेने की भूल न करना। उपचुनाव यही बता रहे हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। जनता जब बदलने का मन बना लेती है, तो केवल उम्मीदवार ही नहीं, वर्षों से बने राजनीतिक मिथक भी बदल जाते हैं।

राजनीति में नई पीढ़ी का आना आवश्यक है, लेकिन अनुभव और संघर्ष को अपमानित करके नहीं। जिस संगठन में त्याग, तपस्या और निष्ठा की जगह केवल तात्कालिक लोकप्रियता या समीकरण ले लेते हैं, वहां पीढ़ियों के बीच दूरी पैदा होती है। नई पीढ़ी ऊर्जा लाती है, लेकिन संगठन की आत्मा उन लोगों में बसती है जिन्होंने वर्षों तक कठिन समय में उसे संभाला होता है। एक और प्रश्न गंभीर है। जिन सामाजिक वर्गों ने वर्षों तक किसी दल को अपना स्वाभाविक राजनीतिक विकल्प माना, यदि वही वर्ग असंतोष व्यक्त करने लगे, तो उसे केवल चुनावी गणित मानकर टालना उचित नहीं होगा। किसी भी समाज की नाराजगी का समाधान संवाद, सम्मान और विश्वास से निकलता है, उपेक्षा से नहीं।

बांकेपुर का परिणाम सबसे बड़ा संकेत देता है। जहां कुछ ही महीने पहले भाजपा को भारी बहुमत मिला था, वहीं उपचुनाव में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं। बांकेपुर, दतिया का चुनाव वास्तव में संगठन और सत्ता की लगाम अपने हाथ में रखने वाले उन चाणक्यों के लिए एक सबक है। हर पुराने को निकाल फेंकने और किसी को भी सामने लाने की परंपरा जहां भी होगी वहां पर एक जेनरेशन गैप तो आता ही है और आज का जनरेशन ना त्याग करना जानता ? ना तपस्या करना जानता ?और ना ही बलिदान ? उन्हें तो बिना सब कुछ किये 'सुघड़' चाहिए। जबकि सियासी चाणक्य सिर्फ थोपना जानते लीपना या पोतना तो हमें ही पड़ेगा !

बिना पैसे और एप्रोच के नौकरी...! ऐसा कभी होता है क्या भला ?

कॉलम - खुरचन

द्वारा- हरिदास

सरकारी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक बनने का सपना देखने वाले युवाओं को अपना सपना वापस ले लेना चाहिए। सपना बहुत महँगा पड़ता है। वर्षों की पढ़ाई, पीएच.डी., परीक्षाएँ, प्रतियोगिताएँ, साक्षात्कार के लिए विशेष तैयारी, दस्तावेजों की जाँच और अंत में पता चलता है कि नियुक्ति के लिए इनमें से किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता थी—पहुँच और पैसों की। आपने नेट किया, पीएचडी की, शोधपत्र लिखे, सेमिनारों में गए, किताबें पढ़ीं। आपने सोचा कि विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए ज्ञान चाहिए। यह आपकी पहली भूल थी। दूसरी भूल थी यह मान लेना कि विज्ञापन में लिखी योग्यता ही वास्तविक योग्यता है। तीसरी और सबसे बड़ी भूल थी यह विश्वास करना कि चयन निष्पक्ष होगा।

सरकारी विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए अब दो तरह के उम्मीदवार होते हैं। एक वे, जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। दूसरे वे, जिनके बारे में तैयारी करने वालों को बाद में पता चलता है कि तैयारी तो उन्होंने पहले ही कर रखी थी—कहीं और। कहीं-कहीं तो ऐसा लगता है कि चयन समिति उम्मीदवार का बायोडाटा नहीं देखती, उम्मीदवार का परिवार-ट्री देखती है। शोध कितना है, दस्तावेज कितने हैं, साक्षात्कार में कितने सवालों का सही जवाब दिया, यह सब बाद में देखा जाएगा; पहले यह देखा जाए कि आपका परिचय किससे है। आपने कितने शोधपत्र लिखे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपके लिए कितने फोन आए।

युवा पूछता है—"सर, मेरी योग्यता?"

व्यवस्था मुस्कराकर कहती है—"बहुत अच्छी है।"

"तो मेरा चयन?"

"वह तो दूसरी योग्यता पर निर्भर करता है।"

"दूसरी योग्यता?"

"आप समझदार हैं, इतना तो समझ ही गए होंगे।"

सबसे मजेदार स्थिति तब होती है जब प्रतीक्षा सूची आती है।

जिस युवा ने सोचा था कि चलो, चयन नहीं हुआ तो शायद प्रतीक्षा सूची में नाम होगा, वह सूची खोलता है। वहाँ भी वही बड़े नाम दिखाई देते हैं। वह सोचता है—"अच्छा! यहाँ भी?"

व्यवस्था कहती है—"भाई, प्रतिभा में भी तो निरंतरता होनी चाहिए। बड़े लोगों का नाम मुख्य सूची में हो या प्रतीक्षा सूची में, परंपरा बनी रहनी चाहिए।" प्रतीक्षा सूची का अर्थ अब यह नहीं रह गया कि यदि चयनित उम्मीदवार नहीं आया तो अगला योग्य उम्मीदवार आएगा। इसका अर्थ है—व्यवस्था के इंतजार में बैठी हुई संभावनाओं की सूची।

एक प्रतिभाशाली युवक ने मुझसे कहा, "मैंने दस साल पढ़ाई की है।"

मैंने कहा, "बहुत अच्छा।"

बोला, "शोध किया है।"

मैंने कहा, "और अच्छा।"

बोला, "नेट-जेआरएफ किया, पीएचडी की, कई शोधपत्र हैं।"

मैंने कहा, "तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है।"

वह बोला, "लेकिन चयन नहीं हुआ।"

मैंने पूछा, "तुम्हारे पास एप्रोच है?"

वह चुप हो गया।

मैंने कहा, "पैसा?"

वह और चुप हो गया।

मैंने पूछा, "किसी बड़े आदमी का आशीर्वाद?"

अब उसकी आँखें भर आईं।

मैंने उसे समझाया—"बेटा, तुम्हारे पास ज्ञान है। यह सबसे खतरनाक चीज है। इसे लेकर विश्वविद्यालय के दरवाजे पर मत जाना। वहाँ इसकी कोई रसीद नहीं कटती। जिस विश्वविद्यालय का नाम किसी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति से जुड़ा हो, वहाँ यदि प्रतिभा अपने आपको बाहरी समझने लगे और पहुँच रखने वाला अपना, तो यह केवल नियुक्ति की समस्या नहीं है। यह उस स्मृति का भी अपमान है जिसके नाम पर संस्थान खड़ा है।

विश्वविद्यालय ज्ञान का किला होना चाहिए था। मगर जब किले की दीवारों में रिश्तेदारी की खिड़कियाँ खुल जाएँ, पहुँच की सीढ़ियाँ लग जाएँ और पैसे की लिफ्ट चलने लगे, तो बाहर खड़ा मेधावी युवक केवल इतना पूछ सकता है—"प्रवेश परीक्षा कहाँ है?"

अंदर से आवाज आती है—"तुम्हारे लिए कोई परीक्षा नहीं है।"

"तो साक्षात्कार?"

"वह भी नहीं।"

"फिर?"

"पहले यह बताओ—तुम किसके आदमी हो?"

युवा कहता है—"मैं किसी का आदमी नहीं हूँ।"

व्यवस्था कहती है—"तो फिर तुम प्रतिभाशाली हो सकते हो, लेकिन हमारे काम के नहीं हो।" यही वह जगह है जहाँ शिक्षा व्यवस्था चौपट होती है। जब विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगें, तो इसका असर केवल कुछ अभ्यर्थियों पर नहीं पड़ता। आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। जिस शिक्षक को योग्यता से अधिक पहुँच ने नियुक्त कराया है, वह कक्षा में विद्यार्थियों को क्या पढ़ाएगा? "जिस दिन बिना एप्रोच और पहुँच के सरकारी नौकरी मिल जाए, समझो रामराज्य आ गया!"

बातों बातों में — साप्ताहिक कॉलम

साला, मैं तो साहब बन गया...

साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया... दिलीप कुमार अभिनीत हिंदी फिल्म का ये गाना सूबे के लालफीताशाहों पर फिट बैठता है। छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है! शासन मौन है, संगठन को सांप सूंघ गया है और दिग्गज जनप्रतिनिधियों का सूबे के बेलगाम नौकरशाहों के खिलाफ बोल-बोलकर गला रुंधने लगा है। कोई नौकरशाह दिग्गज जनप्रतिनिधियों के विशेषाधिकार हनन में मगन है, तो कोई खस्ताहाल महकमे का रखरखाव छोड़कर 45 की उम्र में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी बॉडी बनाने में मस्त है। 10 से ज्यादा

बार फेल होकर IAS बनने वाला 45 की उम्र में हैरान करने वाले बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में जुटा हुआ है। वैसे तो हाउसिंग में एक से बढ़कर एक तोपचंद सचिव रहे हैं, लेकिन किसी ने भी हाउसिंग बोर्ड के जर्जर होते इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। सबसे जरूरी है विभाग की बीमारी दूर करना। विभाग की बीमारी दूर हो जाएगी, तो अफसरों की वजह से हाउसिंग बोर्ड का मकान-दुकान लेने वाले हितग्राहियों की दिक्कतें भी अपने आप दूर हो जाएंगी। यह तभी होगा जब साहब जी जिम में कम और विभाग में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। मंत्री का क्या, वो तो बने रहेंगे।

इंट को विषकन्याओं का हिंट...

छत्तीसगढ़ में भी जिम से लेकर दफ्तर तक और कमर के ढीले साहबों के केबिन तक में विषकन्याओं की घुसपैठ हो गई है। सरकार भी ऐसे रंगीन मिजाजॉन से बेखबर नहीं है, पर मजबूर है, क्योंकि इनके आगोश में चंद पार्टी नेता भी हैं। विषकन्याएं अफसरों और नेताओं को अपने जाल में फंसाकर जो चाहे वो काम करवा रही हैं। कलेक्टर, एसपी समेत कुछ अधिकारियों के बारे में इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास पुख्ता सूचना है। इंट अफसरों को भी ये हिंट हो चुका है। स्टेट का सिस्टम अगर अलर्ट नहीं हुआ, तो एमपी की तर्ज पर सीजी में भी हनीट्रैप का मामला खुलेगा। एनजीओ संचालिका, जिम ट्रेनर और जुंबा सीखते-सिखाते विषकन्याओं के आगोश में कब समाते चले गए, ये खुद वो नहीं जानते। एक कलेक्टर के घर में तो कथित विषकन्या को लेकर बवाल मचा हुआ है।

राम नाम सत्य है, बाकी अस्वस्थ है...

छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य ही है कि 25 साल बाद भी आदिवासी इलाके में लोग मलेरिया जैसी सामान्य बीमारी से मर रहे हैं, तो शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों की स्थिति भी कमोबेश वैसी ही है। कोई 'तोप की नाल' टाइप का भी अगर सचिव बनता है, तो वह एनजीओ और सप्लायरों से इस कदर घिर जाता है कि बाकी चीजों के लिए उसके पास टाइम नहीं बचता। खाली समय में "जो करना है कर लो" वाले अंदाज में झिड़क देते हैं। सीजीएमएससी, हेल्थ डायरेक्टोरेट छोड़िए,

ये तो एमबीबीएस, एमडी डॉक्टरों को आदिवासी इलाके में पदस्थ तक नहीं कर सकते। लेकिन दिग्गज जननेताओं को किसी की सरपरस्ती में फटकार जरूर देते हैं। गांवों में अगर हेल्थ सिस्टम को पहुंचाना है, तो सिस्टम को इसी तरह कुछ करना होगा, वरना विभाग के साथ-साथ सरकार का भी राम नाम सत्य कर देंगे।

कांग्रेस की सुबाई सियासत में युवा या बुढ़वा...

कांग्रेस की सुबाई सियासत में नए समीकरण बन रहे हैं... शतरंज की बिसात पर शह और मात का खेल चल रहा है। पीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं में खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले सीनियर वर्सेस जूनियर चला, अब बुढ़वा बनाम जवान चल रहा है। खैर, पावर के लिए जोर-आजमाइश में महंत, सिंहदेव और बघेल गुट में चल रही रस्साकशी में अचानक युवा ऊर्जावान चेहरे बनकर उमेश पटेल का नाम सामने आ गया। ऐसे में दिल्ली में दखल रखने वाले युवा चेहरों में देवेंद्र यादव और विकास उपाध्याय का नाम भी चर्चा में है। इसके बाद से ही अध्यक्ष पद के युवा दावेदार उमेश पटेल और देवेंद्र यादव के खिलाफ पार्टी नेतृत्व को चिट्ठी-पत्री भेजना तेज हो गया है। आने वाले समय में कांग्रेस की गुटीय लड़ाई और तेज होगी, वो इसलिए कि इन सभी नेताओं की दिल्ली में गहरी पैठ है।

चिंतन और मंथन ; धृतराष्ट्र

जब पैरेंट्स के रूप में हमने अपनी जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा एक ऐसे स्पष्ट उद्देश्य के साथ बिता दिया था, जिसे खोजने की उन्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। यह सफर आधी रात को सुनाई देने वाली एक नन्ही-सी किलकारी से शुरू हुआ था और स्कूल की यूनिफॉर्म, लंच-बॉक्स, होमवर्क, बुखार, परीक्षाओं, कॉलेज में दाखिले, पहली नौकरी, हार्टब्रेक्स, शादी और बच्चों की सैकड़ों छोटी-छोटी जरूरतों से गुजरता हुआ आगे बढ़ा था- ऐसी जरूरतें, जिन्हें शायद बच्चे खुद भी याद न रखते हों। लेकिन माता-पिता उनमें से हर एक को याद रखते हैं। बच्चों की 'जरुरत' पूरी करने और उनके बड़े बन जाने के बाद की जाने वाली उनकी 'जुर्रत' हर पैरेंट को याद रखने के लिए खुद के लिए भी रखना होगा। पालकों के पास अपने जीवन का कोई दूसरा प्रयोजन भी होना चाहिए और अगर वह बच्चे के दूर जाने से पहले ही शुरू हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हमारे बच्चे हमेशा ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं बने रहेंगे। उन्हें अपना जीवन भी जीना है और अपने स्वयं के उद्देश्यों को भी पूरा करना है। उन्हें अपने बच्चे की पसंद की हर डिश याद रहती है। वे जानते हैं कि उन पर कौन-सी दवा असर करती है। वे यह भी समझते हैं कि बच्चा कब ठीक होने का दिखावा कर रहा है। वे मैं ठीक हूं और मैं सचमुच ठीक हूं के बीच का फर्क जानते हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वे वर्षों तक बच्चों की जरूरतों पर प्रतिक्रिया देते रहे हैं- चाहे वे कितनी ही छोटी हों या कितनी ही महंगी।

लश्कर कमांडर कारी सईद की इस्लामाबाद में मौत

इस्लामाबाद। पड़ोसी देश पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के कमांडर कारी सईद उर्फ अब्दुल अज़ीज़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. आतंकी कारी सईद उर्फ अब्दुल अज़ीज़ लश्कर ए तैयबा के शोबा-ए-वारसा-ए-शोहदा विभाग का दक्षिण पंजाब में प्रमुख था, जिसका काम भारत में मारे गए आतंकियों के परिजनों को हर महीने पेंशन देना था. घटना की सीसीटीवी वीडियो एबीपी न्यूज़ के हाथ लगी है जिसमें दिखाई दे रहा है आतंकी कारी सईद उर्फ अब्दुल अज़ीज़ इस्लामाबाद में स्थित लश्कर ए तैयबा की मस्जिद क़ूबा में बैग टांग कर नमाज पढ़ने पहुंचता है. पहुंचने के बाद अपने एक साथी को बैग पकड़ाता है और नमाज़ पढ़ने से पहले वुज़ू करता है. वुज़ू करने के बाद जैसे ही आतंकी कारी सईद उर्फ अब्दुल अज़ीज़ अपना बैग वापस लेकर सीढ़ी चढ़कर मस्जिद के मुख्य हाल में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है. वो जैसे ही चप्पल उतारने के लिए बैठता है वैसे से एकाएक ज़मीन पर गिर जाता है. पास में ही मौजूद लश्कर ए तैयबा के कैडर के अन्य लोग उसे उठाकर किसी जगह पर लेकर जाते हैं, जहां उसे सांस ना चलने पर सीपीआर दिया जाता है. लेकिन इसके बावजूद कारी सईद उर्फ अब्दुल अज़ीज़ होश में नहीं आता है. कारी को बाद में अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है.

मक्का रक्षा समझौते पर भड़का ईरान तो आया तुर्किए का रिएक्शन

मॉस्को। पश्चिम एशिया में अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच ईरान ने पाकिस्तान, तुर्किए और सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुए मक्का रक्षा समझौते को लेकर तीखा रुख अपनाया है, जिसके बाद इस मामले पर अब तुर्किए के विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है. तुर्किए के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा कि तुर्किए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में साइन किए गए मक्का रक्षा समझौता किसी भी तरह से ईरान के खिलाफ नहीं किया है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक रक्षात्मक प्रकृति का समझौता है, जिसका असली मकसद किसी भी देश पर हमला बोलना या उसे खत्म कर देना नहीं है। तुर्किए के विदेश मंत्री हकान फिदान ने शनिवार (8 अगस्त, 2026) को अनादोलू एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सऊदी अरब के रुख के बारे में बताते हुए कहा कि सऊदी अरब ने ईरान पर हमला करने या उसे तबाह करने को लेकर कोई रणनीति नहीं बनाई है।

स्कूल में छात्र ने की फायरिंग- 7 की मौत

बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पास शुक्रवार को एक स्कूल में हुई गोलीबारी में तीन शिक्षकों और तीन छात्रों समेत कम से कम छह लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि स्कूल में गोलीबारी करने वाला हमलावर घायल हुआ था. बाद में पुलिस ने पुष्टि की कि हमलावर की भी मौत हो गई है. घटना बैंकॉक से सटे नॉनथाबुरी प्रांत के बैंक क्रुआई जिले में हुई. BBC की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने अपने जारी बयान में कहा कि यह घटना नॉनथाबुरी प्रांत के बैंक क्रुआई जिले में स्थित डेबसीरिन नॉनथाबुरी स्कूल में हुई. पुलिस ने हमलावर की पहचान स्कूल के ही एक छात्र के रूप में की है।

परिसीमन से क्यों चिंतित हैं दक्षिणी राज्य ?

2026 में केंद्र सरकार ने Delimitation Bill, 2026 लोकसभा में पेश किया था.इस पूरे विवाद के केंद्र में सबसे बड़ा सवाल उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व का है.दक्षिणी राज्यों को आशंका है कि अगर भविष्य में लोकसभा सीटों का पुनर्विन्यास मुख्य रूप से आबादी के आधार पर हुआ, तो जिन राज्यों ने दशकों में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है, उनकी संसद में कुल राजनीतिक हिस्सेदारी घट सकती है. वहीं, ज्यादा आबादी वाले राज्यों को सीटों में अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा मिल सकता है.

क्या है चिंता की वजह

दक्षिणी राज्यों की मुख्य चिंता जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध को लेकर है. तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में पिछले दशकों में प्रजनन दर और जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार में कमी आई है. इसके पीछे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार नियोजन जैसे कारकों की भूमिका रही है.दूसरी ओर, उत्तर भारत के कई राज्यों में इसी अवधि में आबादी अपेक्षाकृत तेज गति से बढ़ी. यही वजह है कि दक्षिणी राज्यों के नेताओं को डर है कि अगर लोकसभा की सीटों का पुनर्विन्यास मौजूदा जनसंख्या के अनुपात में किया गया, तो उन्हें जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने का राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. यह चिंता सिर्फ सीटें कम होने की नहीं है, बल्कि लोकसभा में कुल सीटों के अनुपात और राजनीतिक प्रभाव से जुड़ी है.हालांकि, केंद्र सरकार ने इसका अलग आकलन पेश किया है. अप्रैल 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि प्रस्तावित मॉडल में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने पर दक्षिणी राज्यों की सीटें मौजूदा 129 से बढ़कर 195 हो सकती हैं और कुल सदन में उनका हिस्सा करीब 24% के आसपास बना रहेगा.

आबादी बढ़ने का परिसीमन पर क्या असर पड़ सकता है?

भारत में अलग-अलग राज्यों की आबादी पिछले दशकों में एक समान गति से नहीं बढ़ी है. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दक्षिणी राज्यों की तुलना में अधिक रही है. वहीं, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार काफी कम हुई है. यही अंतर परिसीमन की बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. अगर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का आवंटन आबादी के अनुपात में ज्यादा किया जाता है, तो ज्यादा आबादी वाले राज्यों की सीटों में वृद्धि हो सकती है.दूसरी ओर, कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों की सीटें बढ़ने की रफ्तार अपेक्षाकृत कम रह सकती है. इससे लोकसभा में उनकी कुल सीट हिस्सेदारी घटने की आशंका पैदा होती है.

दक्षिणी राज्य क्या कर रहे हैं?

दक्षिणी राज्यों के नेता लंबे समय से परिसीमन के संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताते रहे हैं. तमिलनाडु में यह मुद्दा खास तौर पर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने परिसीमन पर चर्चा के लिए राज्य के सांसदों की बैठक बुलाई. बैठक में शामिल सांसदों ने केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन कानून का विरोध किया, हालांकि DMK और AIADMK समेत कुछ प्रमुख दलों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी पहले परिसीमन और जनसंख्या प्रबंधन के बीच संबंध को लेकर चिंता जता चुके हैं. उन्होंने कहा था कि परिसीमन और जनसंख्या प्रबंधन को अलग-अलग मुद्दों के रूप में देखा जाना चाहिए.

PM मोदी से मिलेंगे NCP (SP) सांसद, परिसीमन पर बनेगी बात?

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह में प्रवेश के साथ ही परिसीमन विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने और परिसीमन के साथ महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों के बीच एनसीपी (शरद पवार) गुट के सांसदों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक 10 अगस्त को हो सकती है. सांसदों ने प्रधानमंत्री कार्यालय से मुलाकात के लिए समय मांगा है. बताया जा रहा है कि इस बैठक में सांसद अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों की समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों को प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे. हालांकि, सरकार की प्राथमिकताओं में परिसीमन प्रक्रिया भी अहम मुद्दा हो सकती है. बैठक ऐसे समय हो रही है, जब संसद के मानसून सत्र का अंतिम सप्ताह शुरू होने वाला है. एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले पहले ही परिसीमन को लेकर पार्टी के रुख के संकेत दे चुकी हैं. उन्होंने कहा था कि अगर प्रस्तावित बदलावों के तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में समान रूप से बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाती है, तो पार्टी परिसीमन प्रक्रिया का समर्थन करने पर विचार कर सकती है. सुले ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि यदि विधेयक में देशभर में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान किया जाता है, तो एनसीपी (एसपी) इस प्रस्ताव का समर्थन करने पर विचार कर सकती है. उन्होंने यह भी बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा हुई थी.

FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि लोकतंत्र में हम किसी के हाथ नहीं बांध सकते और न ही उनके विचारों को दबा सकते हैं. उन्होंने कहा कि हमारा रुख साफ है कि हम सभी पार्टियों के सामूहिक फैसले को मानेंगे. खरगे ने यह भी कहा कि कांग्रेस विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (FCRA Bill) का विरोध करेगी और सोमवार को विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी.

उत्तराखंड के रुद्रपुर में मल्लिकार्जुन खरगे ने न्यूज एजेंसी एएनआई से युवाओं के विरोध प्रदर्शन पर बात की. छात्रों की गूंज कैंपेन और रांची में JPSC-JSSC उम्मीदवारों के विरोध-प्रदर्शन पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राहुल गांधी ने ही सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था. उन्होंने कोटा का दौरा किया और इससे जुड़े सभी लोगों से मुलाकात की.

खरगे ने कहा कि राहुल गांधी के उठाने के बाद ही इस मुद्दे ने असल में ज़ोर पकड़ा. कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि छात्रों ने भी अपनी मांगें रखी हैं और वे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं. उन्हें राहुल गांधी के कैंपेन और उनसे मिले प्रोत्साहन से फायदा हुआ है. राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी थीं. सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम है कि पढ़ाई करते हो, पैसा डालते हो लेकिन रोजगार के सारे दरवाजे बंद पड़े हुए हैं. मैन्यूफैक्चरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि दुनिया में मेड इन चाइना और वियतनाम दिखेगा लेकिन मेड इन इंडिया नहीं दिखेगा. मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने सारा सिस्टम बंद कर दिया. छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए केपी मैदान में बनाए गए मंच पर राहुल गांधी ने छात्राओं संग संवाद किया. कांग्रेस सांसद ने छात्रों से कहा कि आप भारत की शक्ति हो आप भारत की शान हो।

ममता पर हमला, कार पर फेंके गए पत्थर, लगे 'चोर-चोर' के नारे

कोलकाता। कथित पुलिस कस्टडी में मारे गए पश्चिम बंगाल के हलीसहर में तृणमूल के कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गईं, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों ने उनकी गाड़ी को रास्ते में रोक दिया. जब तक गाड़ी रुकी रही, विरोध प्रदर्शन जारी रहा. रविवार (09. 08. 2026) को प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी पर कीचड़ पोता. जूते चप्पल फेंके. अपशब्द बोले और चोर जैसे नारे लगाए गए. टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने पूरे घटनाक्रम पर कहा है कि यह घटना स्थानीय ग्रामीणों ने नहीं, बल्कि बीजेपी के गुंडों ने रची. इधर, स्थानीय लोगों का कहना है कि ममता एक शांत इलाके में अशांति फैलने आई थीं. इससे हालात बिगड़ गए. ममता ने इस पूरी घटना पर बीजेपी पर आरोप मढ़े हैं।

नेतन्याहू ने ठुकराया ट्रंप का गाजा पीस प्लान

तेल अवीव। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति की योजना को खारिज कर दिया है. इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा को लेकर 15 सूत्रीय बोर्ड ऑफ पीस योजना का प्रस्ताव रखा था . इजरायल की मीडिया के मुताबिक, 'नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हमास के पूरी तरह हथियार डालने तक इजरायली सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी.' उन्होंने कहा, 'इजरायल हमास के वास्तिवक और पूरी तरह खत्म होने की मांग कर रहा है. सिर्फ दिखावटीतौर पर संगठन को कमजोर करने से बात नहीं बनेगी.'इसके अलावा इजरायल के पीएम ने बताया कि इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी है. ट्रंप प्रशासन की कुछ योजनाएं इजरायल को मंजूर है. कुछ पर वह सहमत नहीं हैं.

अलजजीरा के मुताबिक, पिछले हफ्ते अमेरिका के नेतृत्व वाले बोर्ड ऑफ पीस के डायरेक्टर निकोले म्लानदेनोव और नेतन्याहू के बीच हुई मीटिंग के बाद बोर्ड ने कहा है कि गाजा से इजरायली सेना तभी हटेगी, जब हमास के हथियार पूरी तरह से जब्त कर लिए जाएंगे इधर, ट्रंप ने पिछले महीने घोषणा की थी कि युद्ध खत्म करने की उनकी योजना में एक बड़ी कामयाबी मिली है. इस योजना पर इजरायल और हमास ने पिछले साल सहमति जताई थी. इसकी शुरुआत युद्ध विराम से हुई थी. पिछले साल अक्टूबर से सीजफायर होने के बावजूद इजरायल गाजा पर हमले करता रहा है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, 'हमास हथियार डालने पर सहमत हो गया था. हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला करके गाजा युद्ध शुरू करने से पहले लगभग दो दशकों तक शासन किया था.' दरअसल, इजरायल और गाजा के बीच मुख्य रूप से जमीन के अधिकार, संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा विवाद है. ऐतिहासिक आधारों के मुताबिक,1948 में इजरायल की स्थापना के समय करीबन 7 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हुए थे. इनमें से बहुत लोग शरणार्थी बनकर गाजा पट्टी में ही बस गए थे.

चीन को दिया करारा जवाब

अरुणाचल के 27 स्थानों को भारत ने नक्शे में किया शामिल

भारत ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन को एक बार फिर साफ संदेश दिया है. भारत सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे को अपडेट करते हुए चीन की सीमा से जुड़े 27 महत्वपूर्ण स्थानों को भारतीय नामों के साथ दर्ज किया है. इनमें पहाड़ी दर्रे, झीलें, बस्तियां और 1962 के भारत-चीन युद्ध से जुड़ा एक युद्ध स्मारक भी शामिल है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश को 'जंगनान' या 'दक्षिण तिब्बत' बताकर वहां के कई स्थानों के नाम बदलने की कोशिश करता रहा है.

भारत पहले भी कई बार साफ कर चुका है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न हिस्सा है और चीन के नाम बदलने से यह सच्चाई नहीं बदल सकती. ऐसे में नक्शे में 27 स्थानों को भारतीय नामों के साथ शामिल करना सिर्फ नक्शा अपडेट करना नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश पर भारत के दावे और अपनी जमीन पर प्रशासनिक पकड़ को साफ तौर पर दिखाने वाला कदम है. खास बात यह है कि इनमें कई जगहें 1962 के युद्ध और भारत-चीन सीमा पर हुए पुराने संघर्षों से जुड़ी हैं. चीन ने 2017, 2021 और 2023 में अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के लिए चीनी नाम जारी किए थे. भारत ने हर बार इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है. अब भारत ने अपने आधिकारिक नक्शे में संबंधित स्थानों को भारतीय नामों के साथ स्पष्ट रूप से दर्ज किया है. सरकार का कहना है कि

इससे इन स्थानों की सटीक पहचान सुनिश्चित करने के साथ-साथ लोगों में इनके बारे में जागरूकता बढ़ेगी. विवादित सीमा वाले क्षेत्रों में स्थानों के नाम और उनकी पहचान किसी देश की आधिकारिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए यह कदम सिर्फ नक्शे में बदलाव नहीं, बल्कि भारत के प्रशासनिक और क्षेत्रीय दावे का भी स्पष्ट बयान माना जा रहा है.

नक्शे में कौन-कौन से स्थान जोड़े गए?

अपडेट किए गए नक्शे में चार महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रों द्जो ला, रिजा ला, पुकुर ला और थग ला को शामिल किया गया है. इनमें थग ला का विशेष रणनीतिक और ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि 1962 के भारत-चीन युद्ध के शुरुआती चरण में यहां संघर्ष हुआ था. इसके अलावा सांबो सरोवर को भी भारतीय नाम के साथ नक्शे में दर्ज किया गया है. बाकी 21 स्थानों में लॉन्गजू, माजा, बीसा, बड़ा कुंदुन, छोटा कुंदुन, धन बारी, प्रीतनगर, बुद्धमंदिर, जयरामपुर, तेरीतनगर, रामनगर, जसवंत गढ़, सागर, पद्मा, ज्योतिनगर, बैसाखी, छोटा रोपुक, बड़ा रोपुक, शिवाजी नगर, सुनपुरा और कामलंग नगर शामिल हैं. इसके अलावा शेर-ए-थापा मेमोरियल को भी नक्शे में शामिल किया गया है. यह स्मारक 1962 के युद्ध में वीरता दिखाने वाले हवलदार शेर-ए-थापा की याद में बनाया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है. उन्होंने देश के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि हमारा तिरंगा हमारे गर्व और गौरव का प्रतीक है. आइए हम सभी पूरे उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान में भाग लें और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के सामूहिक संकल्प को दोहराएं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रविवार (9 अगस्त, 2026) को इस संबंध में एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा, 'हमारा तिरंगा हमारे गर्व और गौरव का प्रतीक है और यह हमें हमेशा देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की प्रेरणा देता है. आइए, हम सभी पूरे उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लें और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के सामूहिक संकल्प को दोहराएं.' उन्होंने आगे कहा, 'यह बहुत ही खुशी की बात है कि इस साल की यह कोशिश वंदे मातरम् को समर्पित है और वो भी ऐसे वक्त पर जब हम वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं.'

महंगा हुआ दूध, 11 अगस्त से 2 रुपये बढ़ेंगी कीमतें

नई दिल्ली। अभी त्योहारी सीजन शुरू भी नहीं हुआ है कि चीजों की कीमतें बढ़ने लगी हैं. पहले चीनी के दाम बढ़ने की खबरें सामने आईं और अब दूध की कीमतें बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं. महाराष्ट्र में मंगलवार (11 अगस्त) से गाय और भैंस दोनों तरह के दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होने जा रही है. मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर्स वेलफेयर एसोसिएशन' की बैठक में राज्य की प्रमु सहकारी और निजी डेयरियों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है. त्योहारी सीजन में दूध की कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर पूरे राज्य में ग्राहकों पर पड़ने की उम्मीद है. महाराष्ट्र में 2 रुपये की बढ़ोतरी के बाद दूध के खुदरा दाम कुछ इस प्रकार होंगे:- गाय का दूध- 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 62 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा. भैंस का दूध- पहले 76 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 78 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा.एसोसिएशन का कहना है कि दूध के साथ-साथ दही, छाछ, पनीर और घी की कीमतें भी 10% तक बढ़ेंगी. इस बीच, पिछले महीने लोकसभा में एक 'स्टार्ड क्वेश्चन' (जिसका मौखिक जवाब दिया जाता है) के लिखित जवाब में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह (जिन्हें ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है) ने कहा था कि दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और कीमतें बाजार की स्थितियों के अनुसार सहकारी समितियों और निजी डेयरियों द्वारा तय की जाती रहेंगी.

ब्रेट ली ने वैभव के उम्र पर टिप्पणी को बताया बकवास

नई दिल्ली। भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही अपने खेल से क्रिकेट की दुनिया का ध्यान खींच लिया है. अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली भी वैभव के खेल के फैन हो गए हैं. उन्होंने वैभव की उम्र को लेकर होने वाली बहस को बेवजह बताया है. ब्रेट ली ने कहा कि लोगों को वैभव की उम्र पर चर्चा करने के बजाय उनके खेल पर ध्यान देना चाहिए. उनके मुताबिक, अगर वैभव 15 साल के हैं तो यह शानदार बात है और अगर उनकी उम्र 17 या 18 साल भी होती, तो इससे उनके क्रिकेट खेलने की काबिलियत नहीं बदलती. ली ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैभव की उम्र कितनी है. वह सिर्फ इतना देखते हैं कि इस युवा बल्लेबाज में क्रिकेट खेलने की शानदार क्षमता है. न्होंने कहा, 'वह अविश्वसनीय है. भारत के बाहर हर कोई पूछता है कि क्या वह सच में 15 साल का है. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र कितनी है. यह लड़का क्रिकेट खेलना जानता है.'

मिचेल स्टार्क बने 'प्लेयर ऑफ द ईयर'

एडिलेट। 11 टेस्ट में 57 विकेट लेकर स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द ईयर जीते हैं. वहीं मिचेल मार्श वनडे में साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने हैं. ट्रेविस हेड लगातार दूसरी बार 'एलन बॉर्डर मेडल' पुरस्कार जीतने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं. दरअसल, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सभी फॉर्मेट में साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का एलान किया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में एलन बॉर्डर मेडल जीतना एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है. वहीं हेड लगातार दूसरी बार यह अवॉर्ड जीतने में सफल रहे।

भारत ने श्रीलंका इलेवन को 6 विकेट से हराया

दूसरी पारी में चमके गिल और जायसवाल

कोलंबो। भारतीय टीम ने कोलंबो में खेले गए वार्म-अप मैच में श्रीलंका इलेवन को 6 विकेट से हराया. टीम इंडिया को जीतने के लिए 207 रनों का लक्ष्य मिला था. शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने शानदार शुरुआत दिलाते हुए पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की. गिल 44 रन बनाकर आउट हुए, 54 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 7 चौके लगाए. उनका मैदान पर उतरना ही टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर थी, वह उंगली में चोट के कारण पहली पारी में बल्लेबाजी करने नहीं आए थे. अभ्यास मैच में उनकी जगह केएल राहुल ने कमान संभाली. आखिरी समय में मैच रोमांचक हो गया. जीतने के लिए 16 रन चाहिए थे और सिर्फ 6 गेंदों का खेल बाकी थी. मोहम्मद सिराज ने छक्कों की बारिश कर मैच जिता दिया.

आज तीसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 357 रनों पर घोषित कर दी थी. श्रीलंका इलेवन के पास पहली पारी के आधार पर 6 रनों की बढ़त थी. श्रीलंका के लिए दूसरी पारी में ओपनर निशान फर्नांडो ने 63 रन बनाए, वह रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे. दूसरी पारी में भारत के लिए गुरनूर बरार और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए थे. भारत को जीत के लिए 207 रनों का लक्ष्य मिला था.

दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरे गिल

भारत के लिए आज सबसे अच्छी खबर ये आई कि शुभमन गिल बल्लेबाजी पर उतरे. बता दें कि मैच से पहले फील्डिंग के अभ्यास के दौरान उनकी उंगली में चोट लग गई थी. वह पहली पारी में नहीं खेले, न ही फील्डिंग की. उनकी जगह केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे. आज बल्लेबाजी करते हुए गिल ने 44 रन बनाए, वह अच्छी लय में दिखे. इस पारी में उन्होंने 7 चौके लगाए. पहली पारी में शून्य पर आउट होने वाले यशस्वी जायसवाल ने 46 गेंदों में 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से 61 रन बनाए, वह रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे. तीसरे और आखिरी दिन का आखिरी ओवर बचा था, भारत को जीतने के लिए 16 रन चाहिए थे. मोहम्मद सिराज ने शुरूआती 3 गेंदों में 3 छक्के लगाकर मैच जिता दिया. सिराज ने 15 गेंदों में 32 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 4 छक्के लगाए. हालांकि भारत की ये जीत रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगी. दरअसल ये वार्म-अप मैच था, जिसमें खिलाड़ियों के प्रदर्शन और टीम की जीत गिनी नहीं जाती. दूसरी पारी में भारत के लिए एक और अच्छी बात ये रही कि तेज गेंदबाजों ने भी विकेट निकाले. मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को 1-1 विकेट मिला. पहली पारी में दोनों कोई विकेट नहीं ले पाए थे।

रहाणे का खुलासा, यशस्वी जायसवाल पर लगने वाला था 4 मैच का बैन

नई दिल्ली। संन्यास के बाद अजिंक्य रहाणे ने यशस्वी जायसवाल से जुड़े एक पुराने विवाद को लेकर खुलासा किया कि उन पर 4 मैच का बैन लग सकता था. उनके ऊपर होने वाले एक्शन को लेकर चिट्ठी भी लिखी जा चुकी थी. बता दें कि 2022 दलीप ट्रॉफी फाइनल में रहाणे ने जायसवाल को मैदान से बाहर कर दिया था. ये स्लेजिंग से शुरू हुआ, जिसमें हालात बिगड़ने के बाद वेस्ट जोन के लिए कप्तानी कर रहे रहाणे को बीच में आना पड़ा. उन्होंने अपने खिलाड़ी जायसवाल को ही बाहर कर दिया, अब उन्होंने खुलासा किया कि वह अगर ऐसा नहीं करते तो उनपर बैन लगना तय था. 2022 दलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन और साउथ जोन के बीच फाइनल हुआ था. इस मैच में यशस्वी जायसवाल साउथ जोन के बल्लेबाज रवि तेजा को स्लेज कर रहे थे. अंपायर द्वारा कई बार चेतावनी देने के बाद भी यशस्वी नहीं रुके. अजिंक्य रहाणे को बीच में आना पड़ा, जो वेस्ट जोन के कप्तान थे. अब संन्यास के बाद रहाणे ने उस विवाद को लेकर खुलकर बात की और बताया कि यशस्वी पर बैन लग जाता अगर वह उन्हें मैदान से बाहर नहीं करते.एक इंटरव्यू में रहाणे ने कहा, "उस समय यशस्वी को बुरा लगा होगा. खेल में स्लेजिंग होती है, इससे मजा आता है और ये होना भी चाहिए लेकिन उस समय ज्यादा हो रहा था. हमने पहले भी कई बार देखा है जब खिलाड़ियों पर इस तरह की चीजों के लिए बैन लग जाए।

CWG 2026 के पदक विजेताओं से मिले PM मोदी, दी बधाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सभी पदक विजेताओं से मुलाकात की. पीएम ने सभी के साथ मिलकर एक वीडियो भी बनाया और देश के नाम एक संदेश भी दिया. उन्होंने कहा, "जो खेलेगा, वो खिलेगा." वीडियो में साक्षी चौधरी ने प्रधानमंत्री से कहा कि, "सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. आप बहुत विनम्र हैं." साक्षी चौधरी ने कहा, "कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले हम सभी खिलाड़ियों को आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया है. हमें इस बात पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है. हमें इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। सर बहुत ही विनम्र हैं." इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से कुछ कहने के लिए कहा.प्रधानमंत्री ने कहा, "जो खेलेगा, वो खिलेगा। हमेशा भारत को चीयर करो." इसके बाद उन्होंने भारत माता की जय का जयघोष किया. उनके साथ सभी खिलाड़ियों ने भारत माता की जय का जयघोष किया.

बुमराह-सुदर्शन नहीं, टीम इंडिया के 13 खिलाड़ी हैं चोटिल

नई दिल्ली। बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बीते कुछ दिनों से सवालों के घेरे में है. आरोप लग रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ियों की रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया को सही से मैनेज नहीं किया गया, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सीनियर प्लेयर्स के लिए अलग फिटनेस मापदंड तय किए गए. जसप्रीत बुमराह को लेकर पहले कहा गया था कि वह श्रीलंका दौरे से पहले फिट हो जाएंगे, लेकिन फिर स्क्वॉड में शामिल करने के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया. अब साई सुदर्शन बाहर हो गए हैं. वह श्रीलंका दौरे पर टीम के साथ नहीं गए थे, वह अभी भी बेंगलुरु में हैं. खिलाड़ियों की चोट ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा रखी है. अब खबर आई है कि 2-3 या 5 नहीं बल्कि पूरे 13 खिलाड़ी अभी Coe में हैं जो रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.

AI सेक्टर में भी हाहाकार! 66% कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर

नई दिल्ली। AI ने नौकरी की दुनिया में बड़ा बदलाव किया है. कंपनियां तेजी से AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल ज्यादा कर रही हैं.लेकिन अब AI के जगह में काम करने वाले कर्मचारियों को भी नौकरी जाने की परेशानी सताने लगी है. AI और मशीन लर्निंग से जुड़े 66% कर्मचारियों को डर है कि अगले 3 से 6 महीनों में उनकी टीम में छंटनी हो सकती है या कर्मचारियों की संख्या कम की जा सकती है. ये सर्वे प्रोफेशनल कम्युनिटी ऐप Blind ने किया है. जुलाई 2026 में भारत में काम करने वाले 1,552 कर्मचारियों से उनकी नौकरी की सेफ्टी को लेकर सवाल पूछे गए. सर्वे में सामने आया कि AI के जगह में काम करने वाले लोगों को भी नौकरी जाने का डर उतना ही है, जितना उन जगहों के कर्मचारियों को है जिन्हें AI से ज्यादा इफेक्ट होने वाला माना जाता है.सर्वे के मुताबिक, सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े 68% कर्मचारियों को अगले 3 से 6 महीनों में छंटनी या कर्मचारियों की संख्या घटने का डर है.इसके बाद AI और मशीन लर्निंग का नंबर आता है।

क्या भारत में रूक जाएगी तेल की सप्लाई?

नई दिल्ली। रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी सीनेट में पास हुए नए प्रतिबंध विधेयक को लेकर कमोडिटी डेटा एनालिटिक्स फर्म Kpler के एनालिस्ट सुमित रितोलिया ने कहा है कि अमेरिकी सीनेट के इस वोट से रूसी क्रूड ऑयल की सप्लाई में जोखिम जरूर बढ़ा है, लेकिन राहत की बात यह है कि इससे भारत और चीन को होने वाली तेल की सप्लाई में तुरंत कोई बदलाव आने की संभावना कम है.

अमेरिकी सीनेट में बहुमत से पास हुआ बिल

शुक्रवार को अमेरिकी सीनेट ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक बिल पास किया। इस बिल के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों से होने वाले इंपोर्ट पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिलेगा, जो रूस के तेल और गैस के दुनिया के सबसे बड़े खरीदार हैं. 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2026' का मकसद रूसी एनर्जी के पांच सबसे बड़े खरीदारों पर कार्रवाई करना और तेल व गैस की बिक्री से मॉस्को की कमाई को कम करना है, जिससे उसके लिए यूक्रेन में युद्ध के लिए फंडिंग करना मुश्किल हो जाए.

बिल के सामने कई कानूनी अड़चनें

सुमित आगे कहते हैं कि यह बिल भले ही अमेरिकी सीनेट में भारी बहुमत से पास हो गया है, लेकिन इसके साने अभी कई कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें हैं. बिल को अभी अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी कि US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी मिलना बाकी है. इसके बाद ही इसे अंतिम रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि बिल का असर काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि US प्रशासन इन्हें कितनी सख्ती से लागू करता है और क्या वह कोई छूट या रियायत देता है.

घबराने की जरूरत नहीं, सरकार आपकी मदद करेगी

गलती से हो गए किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर, तो क्या करें?

नई दिल्ली। ऑनलाइन बैंकिंग और UPI के बढ़ते इस्तेमाल के चलते कई बार लोग जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं. पैसे ट्रांसफर करते समय किसी गलत खाते में पैसे भेज देते हैं और फिर परेशान होते हैं. लेकिन ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है. अगर समय रहते सही कदम उठाए जाएं, तो पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसा हम नहीं कहते बल्कि सरकार भी इसमे आपकी पूरी तरह से मदद करती है. आइये बताते हैं कैसे?

गलत खाते में हो जाए ट्रांसफर तो क्या करें?

अगर किसी भी तरह की गलतीसे आपसे किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएं, तो ज्यादा परेशान ना होकर बस कुच जरूर दम उठाएं, जैसे:

- सबसे पहले अपने बैंक की कस्टमर केयर या नजदीकी शाखा से संपर्क करें. ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, समय और राशि की जानकारी दें.
- अगर भुगतान UPI से किया है, तो संबंधित ऐप में 'रेज कम्प्लेंट या रिपोर्ट एन ईश्यू का ऑप्शन इस्तेमाल करें.
- शिकायत करते समय रसीद और ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट आपके काम आएंगे, इन्हें संभालकर रखें.
- बैंक को बताएं कि पैसा किस खाते में चला गया है, ताकि वो संबंधित बैंक से संपर्क कर सके.
- अगर UPI लेनदेन से जुड़ा मामला है और बैंक से समाधान नहीं मिलता, तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है.
- अगर आपको धोखाधड़ी का संदेह है या किसी फर्जीवाड़े के कारण पैसा गया है, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करें.
- अगर बैंक तय समय में समाधान नहीं देता, तो आप आगे RBI में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

बैंक और सरकार करेगी पूरी मदद

अगर ट्रांसफर किया गया पैसा किसी वैध खाते में गलती से गया है, तो बैंक आपकी ओर से संबंधित खाताधारक से संपर्क कर सकता है. हालांकि, बिना खाताधारक की सहमति के बैंक सीधे उसके खाते से पैसा वापस नहीं निकाल सकता. इसलिए जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, समाधान की संभावना उतनी अधिक होगी।

ध्यान से करें ट्रांसफर

कोशिश करें कि ऐसा कुछ आपको ना करना पड़े. जब भी किसी को पैसे भेजने हों तो पहले अकाउंट नंबर, IFSC और UPI आईडी को कम से कम एक बार जरूर चेक कर लें. छोटी-सी सावधानी आपको बड़ी वित्तीय परेशानी से बचा सकती है.

टैक्स में छूट वाला बिल पास, रुपये होगा मजबूत

नई दिल्ली। भारत सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा में एक बिल पास किया है. जिसके बाद अब विदेशी निवेशकों को खूब फायदा होगा और वो भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे. टैक्सेशन एंड अदर लॉ (अमेंडमेंड) बिल, 2026 को पास करने का मकसद विदेशी निवेशकों को भारत के सरकारी बॉन्ड में निवेश के लिए आकर्षित करना और देश में फॉरेन रिटर्न एक्सचेंज को बढ़ाना है. इस बिल को लेकर विपक्ष का विरोध भी देखा गया, जिसके बाद लोकसभा में इसे वॉइस वोट के आधार पर पास किया गया. ये बिल 5 जून को जारी किए गए अध्यादेश की जगह लेगा. इस बिल के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII/FPI) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (BIS) को सरकारी बॉन्ड में निवेश से होने वाले ब्याज और कैपिटल गेन पर टैक्स से छूट दी जाएगी. इससे भारत के सरकारी बॉन्ड विदेशी निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनेंगे. सरकार का मानना है कि इस कदम से भारत में ज्यादा विदेशी निवेश आएगा. इससे सरकार को कम लागत पर उधार लेने में मदद मिलेगी, रुपये पर दबाव कम होगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. हाल ही के वैश्विक आर्थिक हालात और बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है.

यादवों के लोक रंजन का सशक्त माध्यम बांसगीत

बुधराम यादव

छत्तीसगढ़ में यादवों को पशुपालन एवं चरवाहा संस्कृति विरासत में मिली है। यादवों के शौर्य, श्रृंगार और प्रेम गाथाओं से युक्त पारंपरिक अवधारणाओं से बांस गीत लोक रंजन का सशक्त माध्यम है। इसके अंतर्गत गाए जाने वाले छहुरा गाथा, मुकुंदा ठेठवार, लोरिक चंदा, लीली बछेरी, फूलबासन कैना जैसे अन्य लोकगीत गाथाएं बांसगीतों की विशिष्टता को प्रमाणित करते हैं।

बांस गीतों में मानवीय सम्बन्धों का लगाव-विलगाव, श्रृंगार-वियोग, प्रेम और विरोध के सन्दर्भ को वर्णनात्मक शैली में रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।

येहू जनम मोर जनम जनव,
दुनों जनम हे अहीर हो।
गोबर, गोधन मोरे अंग म लोटय अउ
गोरस भीजय शरीर हो।
जनम के करिया मै,
करम के हिंहा मै ओ
सेवा बजावत तोर मै
जिनगी पहावत हो ओ।

बांस वाद्य सामान्य बांस से बनाया गया 4 से 5 फिट लम्बा भीतर से पोला टुकड़ा होता है। इसके मध्य से अग्र भाग में 4 छेद होते हैं। जिस पर अंगुलियां नचाकर जिक्का के सहयोग से वादक अनेक तरह से धुन निकालते हैं। अधिकांश बांस आकार में टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसके पीछे स्वर संयोजन और धुन का संतुलन बनाए रखने की मंशा होती है।

दण्डकारण्य के प्रभावी राजा थे शबर

डा. मन्नूलाल यदु

राजा शबर दण्डकारण्य के प्रभावी राजा थे। राजा शबर की बेटी का नाम शबरी था। शबरी बचपन से विदुषी कन्या थी। भगवान श्रीराम के प्रति निष्ठापूर्वक श्रद्धा और विश्वास करती थी। राजा शबर अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे, किन्तु यह शबरी को मंजूर नहीं था। वह घर से निकल कर जंगल की ओर चली गई।

शबरी एक दिन पम्पा नामक सरोवर के तट पर रमणीय मतंग ऋषि के आश्रम मतंग वन पहुंची। यह आश्रम गुरुकुल के रूप में काफी विख्यात था, जहां देश विदेश के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। शबरी ने मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनसे शरण मांगी। ऋषि ने अनुरोध स्वीकार करते हुए अपने आश्रम में शरण दे दी। शबरी ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण थी।

भगवान श्रीराम के वनवास काल में चित्रकूट निवास के समय मतंग ऋषि अपना शरीर त्याग कर परलोक सिधार गए। अंतिम समय में उन्होंने गुरुकुल की जिम्मेदारी सौंपते हुए शबरी को ज्ञान दिया कि तुम एक विदुषी आचार्या हो, इस गुरुकुल आश्रम में श्रीराम और लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर आने पर उनका स्वागत करना, उनके दर्शन से अपने जीवन को सफल बनाना। ऐसा कह कर मतंग ऋषि ने शबरी के हृदय में राम भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित कर दी। कठिन तपस्या के बाद वृद्धावस्था में भगवान राम को सामने पाकर शबरी आत्मविभोर हो गई। अपनी बूढ़ी आंखों से उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि साक्षात प्रभु श्रीराम सामने हैं।

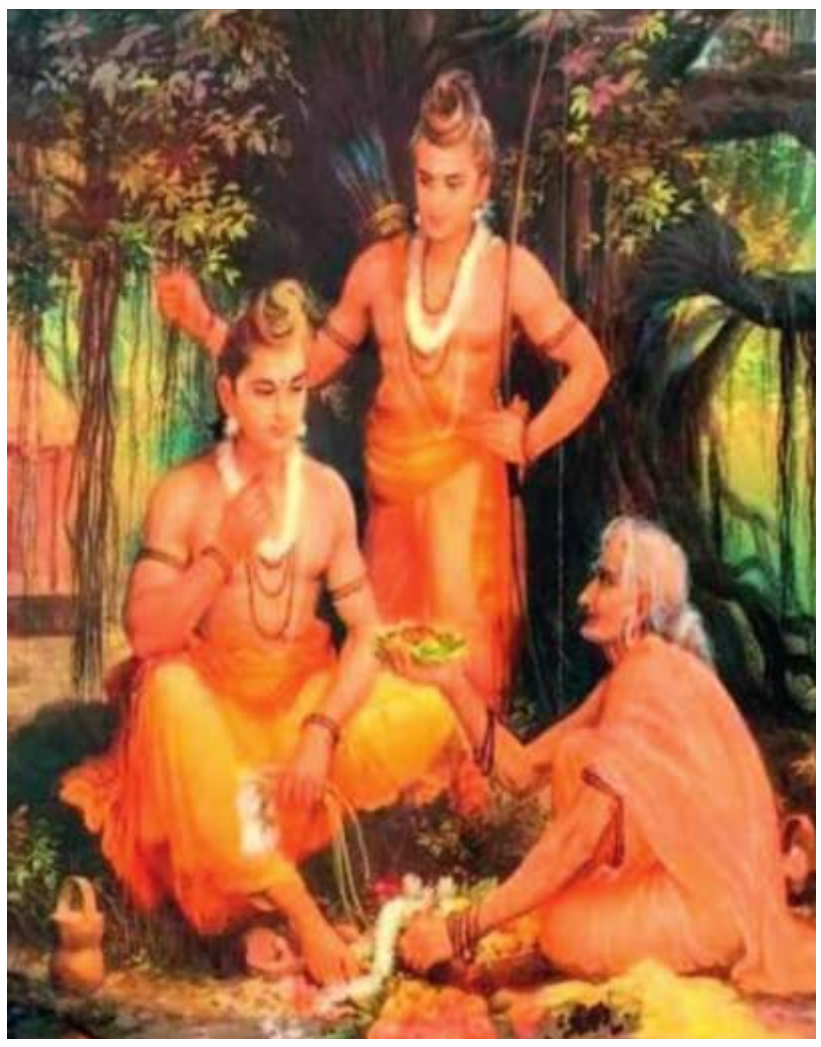

बरसात के दिनों में दिलों को लुभाता कोड़ा खड़का जलप्रपात

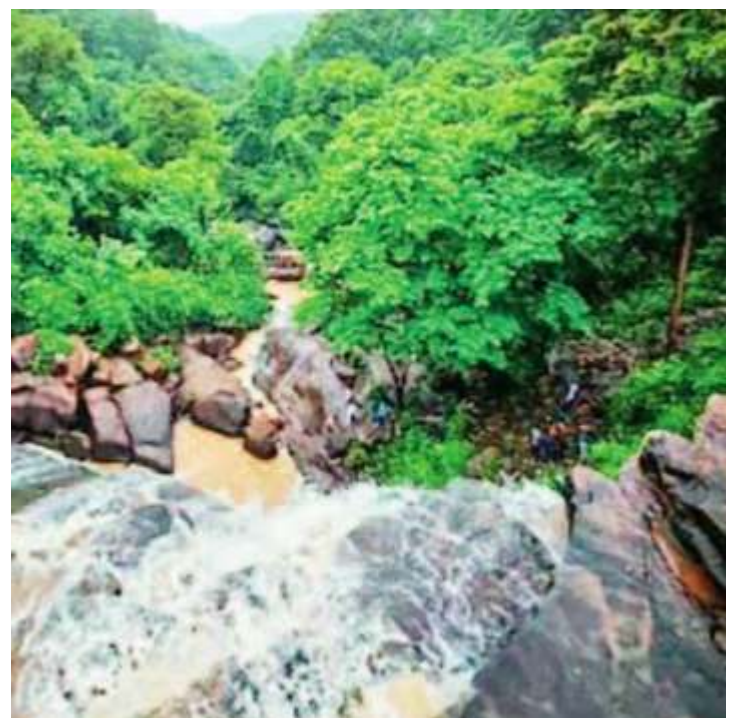

घनश्याम सिंह नाग

बस्तर अंचल के केसकाल क्षेत्र में अनेक झरने और जलप्रपात हैं। यह स्थल दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण आम लोगों का जाना संभव नहीं हो पाता। यहां तक पहुंचने के लिए दो पहिया और चार पहिया वाहन का उपयोग भी नहीं किया जा सकता। इसी कारण बाहर के लोगों के लिए अज्ञात हैं। इन्हीं जल प्रपातों में कोड़ा खड़का जलप्रपात भी है जिसे स्थानीय भाषा में घूमर भी कहा जाता है। यह जलप्रपात प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मनोहारी लगता है। यह कई छोटे छोटे नालों से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेता है। केशकाल से इसकी दूरी 24 कि मी है। इस जलप्रपात तक पहुंचने की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थानीय को छोड़ कर बाहरी पर्यटक नहीं पहुंच पाते। पास पास में और कई घूमर भी देखने लायक है। इस जलप्रपात के पास ही लयाह मत्ता नामक पहाड़ी पर आदि मानव निर्मित शैलचित्र भी देखे जा सकते हैं।

बरसाती भैया नाव ले पहचान बनईन केसरी बाजपेयी जी

चंपेश्वर गोस्वामी

आकाशवाणी रायपुर के जाने माने उद्घोषक रिहिन केसरी प्रसाद बाजपेयी जी। आप मन बरसाती भैया के नाव ले अपन अलग पहचान बनाइन। आपके जनम राजनांदगांव म होय रिहिस। आप आलेख लेखन करत 1950 म आकाशवाणी नागपुर ले सेवा के शुरुआत करेव। आकाशवाणी नागपुर में छत्तीसगढ़ी के कार्यक्रम ल लोकप्रिय बनाय अउ इहा के कलाकार मन ल आगू लाय म आपके बड़ योगदान रिहिस। गुड़ी के गोठ, फुलहेरा अउ लहरिया कार्यक्रम के माध्यम ले दमदार प्रस्तुति ले सांस्कृतिक चेतना जगाय म योगदान दिन।

नवा मध्यप्रदेश बने के बाद 1959 में बाजपेयी जी आकाशवाणी भोपाल आगे। बाद में 1964 में आकाशवाणी रायपुर में छत्तीसगढ़ी प्रसारण के मुख्य दायित्व के काम संभालीन। आकाशवाणी रायपुर ले छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम के माध्यम ले बरसाती भैया के नाव ले गांव गांव के किसान, ग्रामीण लोगन मन के बीच लोकप्रिय होइन। अपन छत्तीस बछर के सेवा काल म छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार संग सांस्कृतिक योगदान म आपके महत्वपूर्ण भूमिका रिहिस। सामाजिक दायित्व के निर्वहन करे म घलो आपके उल्लेखनीय कारज रिहिस। कतको आयोजन आप कला अउ संस्कृति खातिर करात रहेव। आप सुघर कलाकार घलो रहेव। मुंशी प्रेमचंद के कहानी सदगति ऊपर सत्यजीत रे के निर्देशन में टेली फिल्म मे काम करेव। एकरे संग वीडियो फिल्म पुन्नी के चंदा, मां बमलेश्वरी, पिंजरा के मैना में अभिनय करिन। बाजपेयी जी रेडियो के माध्यम ले छत्तीसगढ़ी के जउन सेवा करिन ग्रामीण मन मा अपन जगा बनाइन ओखर सेती आपके नाव सदा अमर रही।

सुवारथ ले ऊपर उठके साहित्य सेवा म ही सबके भलाई हे

छगन लाल सोनी

आज के भाषा पतपरिका मन सालो साल ले चलत आवत हे। फेर हमन तो अपने ले नई ऊपरत हन। करे के पहिली देखथन एमा हमला का मिलत हे, मिले के होही त करबो। पाए के पाछू फेर येला सेवा के नाव देथन। जिंहा सुवारथ हे उन्हा सेवा कईसे होही। देश बर मरैया कूहू मिले के, खाय के सोचतिन त हमन का आजादी पातेन। इही सेवा के भाव आ जाय त भाषा के विकास ल कोन रोक सकत हे। जतका मेहनत अउ दिमाग़ हम अपन आप ल देखाय म, पाय म लगाथन कूहू ओतका दिमाग़ साहित्य सिरजन म लगातेन त अउ ज्यादा हमला उचहा परिणाम देखे बर मिलतिस। नानकन पढ़इया लइका ल जतका जोजियाय ल परथे वईसने ईंहा के सियान मन ल जोजियाय ल परथे। तबो ले पढ़े नहीं। उलटा एके ठन राग ल घेरी बेरी अलापना छत्तीसगढ़ी ल आठवीं अनुसूची म शामिल करे जाय। हीरा ल हम पाबो, फेर बोला पहचाने के परख तो हमर बुद्धि ल होना चाही। छत्तीसगढ़ राज के रहइया जम्मो झन चाहत हे कि ईंहा विकास के गंगा बोहाय। येखर बर तो हमला खुद भगीरथी बने ल परही। एमा भिड़ना तो हमी मन ल हे। येकर ले दूसर विकास के संगे संग भाषा के विकास तको होही ये तो जाने के बात आय।

छत्तीसगढ़ में पांडवों ने किया राज

बाबू मावली प्रसाद

इतिहास के अनुसार पांच पांडवों में से अर्जुन का पुत्र बब्रूवाहन चित्रांगदपुर में राज्य करता था। सिरपुर का दूसरा नाम चित्रांगदपुर था। राजिम और सिरपुर में मिले लेखों से विदित होता है कि यह चौथी शताब्दी में राज्य करते थे। इस वंश के पहले राजा का नाम इंद्रबल था। सिरपुर के गंधेश्वर मंदिर की परिक्रमा की दीवार में इस वंश का वृक्ष एक लेख में दिया गया है जो इस प्रकार है - इंद्रबल 319 ईस्वी, नंददेव 350 ईस्वी, तिवरदेव 375 ईस्वी, हर्षगुप्त 400 ईस्वी, शिवगुप्त 425 ईस्वी, भावगुप्त 450 ईस्वी। चंद्रगुप्त के पौत्र शिवगुप्त का नाम महाशिवगुप्त और नागार्जुन भी था। उसकी माता मगधदेश की राजा की लड़की थी। विधवा होने पर उसने सिरपुर में ईंटो से एक विशाल लक्ष्मण मंदिर बनवाया, जो आज तक दर्शनीय है।

पहली बार बस्तर के 92 गांवों में लहराएगा तिरंगा

500 से ज्यादा स्कूल और चौक-चौराहों का के नाम पर होगा, रायपुर में तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल

शहर सत्ता/रायपुर। माओवाद और नक्सलवाद के खौफ से त्रस्त रहा छत्तीसगढ़ का बस्तर अब नक्सलमुक्त है। नक्सल हिंसा के दौर में जहां आज़ादी के बाद से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराया गया इस बार ऐसे 92 गांवों में 15 अगस्त को पहली बार तिरंगा लहराया जायेगा। बीजापुर में 33 और सुकमा के 50 गांवों समेत नारायणपुर के 9 गांव में तिरंगा फहराया जायेगा।

इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बस्तर के 500 से ज्यादा स्कूलों, प्रमुख चौक-चौराहों और सामुदायिक भवनों का नामकरण भी शहीदों के नाम पर किया जायेगा। उप-मुख्यमंत्री अरुण साव और गृहमंत्री विजय शर्मा ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'हर घर तिरंगा' और 'तिरंगा यात्रा' अभियान की रुपरेखा साझा किये।

10 अगस्त को तिरंगा यात्रा

राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव से 10 अगस्त को सुबह 10 बजे तिरंगा यात्रा प्रारम्भ होगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समेत सभी सांसद, मंत्री और विधायक के अलावा विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स, पूर्व सैनिक, खिलाडी, स्वयंसेवी संस्थाएं, धर्माचार्य भी सामाजिक संगठनों के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे।

15 अगस्त को मुख्यमंत्री साय रायपुर में फहराएंगे तिरंगा

छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 15 अगस्त 2026 को प्रदेश के अलग-अलग जिला मुख्यालयों में होने वाले मुख्य समारोह में कौन-कहां ध्वजारोहण करेगा, इसकी सूची सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है। जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री, डिप्टी CM, मंत्री, सांसद और विधायक अलग-अलग जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। राजधानी रायपुर में 15 अगस्त का मुख्य समारोह आयोजित होगा। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का संदेश भी प्रदेशवासियों के नाम होगा।

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। वे यहां तिरंगा फहराएंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं डिप्टी CM अरुण साव दुर्ग में ध्वजारोहण करेंगे। सरकार के एक अन्य उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा बस्तर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

हिंसा छोड़ मुख्यधारा में लौटे युवा

नारायणपुर में 13 आत्मसमर्पितों को मिले ₹24.30 लाख के चेक, 50 युवाओं के लिए ₹70.68 लाख मंजूर

शहर सत्ता/रायपुर। हिंसा का मार्ग त्यागकर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं के जीवन में नया उजियारा लाने की दिशा में नारायणपुर जिले ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। शासन की पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर शस्त्रों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले 50 पूर्व कैडर के लिए कुल 70 लाख 68 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। इसी पहल के तहत 07 अगस्त को नगर पालिका अध्यक्ष एवं कलेक्टर ने 13 आत्मसमर्पित युवाओं को उनके द्वारा समर्पित हथियारों के एवज में 24 लाख 30 हजार 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि ससम्मान वितरित की।

मुख्यधारा से जुड़कर संवर रहा भविष्य

छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति भटक चुके युवाओं को भयमुक्त और स्वावलंबी जीवन जीने का सुअवसर प्रदान कर रही है। आत्मसमर्पण करने वाले नागरिकों को रोजगार, स्वरोजगार तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से स्थायी रूप से समाज की प्रगति से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य गढ़ सकें।

शांति और विकास ही जीवन की असली राह- कलेक्टर

कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर नारायणपुर ने आत्मसमर्पितों का सहर्ष स्वागत करते हुए उन्हें शासकीय योजनाओं का पूर्ण लाभ उठाकर गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हिंसा छोड़ विकास का मार्ग अपनाना क्षेत्र में शांति, खुशहाली और प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि शेष पात्र हितग्राहियों को भी जल्द ही नियमानुसार स्वीकृत राशि प्रदान की जाएगी। जिले में शांति, विश्वास और पुनर्वास के इस दौर से क्षेत्र में खुशहाली का नया माहौल बन रहा है।

UPI उपयोगकर्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा

व्यापारियों के लिए भी अधिकांश UPI लेन-देन शुल्क-मुक्त रहेंगे

नई दिल्ली। भारत सरकार स्पष्ट रूप से यह कहना चाहती है कि UPI के माध्यम से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं पर किसी भी प्रकार का लेन-देन शुल्क नहीं लगाया जाएगा। UPI के माध्यम से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को किसी भी लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) लेन-देन निःशुल्क रहेंगे। सभी व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) लेन-देन पहले की तरह निःशुल्क रहेंगे।

व्यापारियों के लिए MDR केवल सीमित लेन-देन पर

जब भी MDR (Merchant Discount Rate) लागू किया जाएगा, यह केवल एक निर्धारित सीमा से अधिक के सीमित श्रेणी के व्यापारी लेन-देन पर लागू होगा। इसकी दर मामूली होगी और डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर लागू MDR की तुलना में काफी कम होगी। UPI पर अधिकांश व्यापारी लेन-देन शुल्क-मुक्त रहेंगे। यदि MDR लागू किया जाता है, तो इसे सभी लेन-देन पर एक समान रूप से नहीं लगाया जाएगा, बल्कि यह निर्धारित सीमा के आधार पर ही लागू होगा। संसद द्वारा कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किए जाने के बाद, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A में संशोधन का प्रस्ताव करता है, MDR से संबंधित निर्णय, यदि कोई हो, NPCI की अध्यक्षता वाली "UPI और सेवा संचालन समिति" (UPI and Services Steering Committee) द्वारा लिया जाएगा।

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन क्यों?

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (PSS Act) में हालिया संशोधन को लेकर चर्चा हुई है। कुछ लोगों ने इसे आम उपयोगकर्ताओं पर शुल्क लगाने के कदम के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। वास्तव में, यह संशोधन एक सक्षम प्रावधान है, जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नयन और उभरते जोखिमों के प्रति इसकी क्षमता एवं लचीलेपन को सुनिश्चित करना है।

भ्रामक दावों और गलत धारणाओं पर स्थिति स्पष्ट

कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह सुझाव दिया गया है कि नीतिगत बदलावों के पीछे बाहरी प्रभाव हो सकते हैं। यह पूरी तरह निराधार, असत्य और भ्रामक है। यदि बाहरी दबाव किसी भी प्रकार का कारक होता, तो सरकार वर्ष 2016 में UPI की शुरुआत नहीं करती। साथ ही, जनवरी 2020 से इसे व्यापारियों और नागरिकों दोनों के लिए शुल्क-मुक्त बनाए रखने तथा इसे दुनिया की सबसे बड़ी रियल-टाइम इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली के रूप में विकसित करने के प्रयास भी नहीं किए जाते। PSS Act में संशोधन को सरकार के उस व्यापक उद्देश्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसके तहत भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को टिकाऊ, प्रतिस्पर्धी, नवाचार-समर्थ और देश की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1400 से अधिक महिला कर्मचारियों का हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य एवं कैंसर जांच

जिला प्रशासन की सराहनीय पहल "प्रोजेक्ट अभया"

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा 'प्रोजेक्ट छांव' के अंतर्गत 'प्रोजेक्ट अभया' का शुभारंभ किया गया। इसके तहत आज सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में विभिन्न विभागों की महिला कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों का स्वास्थ्य एवं कैंसर जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 1400 से अधिक महिलाओं ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया।

शासकीय कार्य के साथ स्वास्थ्य भी ज़रूरी, समय पर जांच से संभव है कैंसर का ईलाज - कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुष संचालनालय के डायरेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न वर्गों तक लाभ पहुंचाने के लिए नवाचार किए जा रहे हैं। 'प्रोजेक्ट अभया' उसी का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि माताएं और बहनें घर एवं कार्यालय के काम में व्यस्त रहने के कारण अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पातीं। इसी को ध्यान में रखकर 40 वर्ष से अधिक की शासकीय महिला कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के लिए ब्रेस्ट कैंसर, ओरल और सर्वाइकल कैंसर की निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी बीमारी का समय पर पता चलना बहुत जरूरी है। कैंसर जैसी बीमारी का जितना जल्दी पता चलेगा, उतना ही इलाज आसान होगा। महिलाओं से अपील की कि वे बढ़-चढ़कर जांच कराएं और स्वस्थ रहें। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि 'प्रोजेक्ट अभया' के माध्यम से 40 वर्ष से अधिक की महिलाओं का ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर की निःशुल्क स्क्रीनिंग की जा रही है। यह शिविर आगामी दिनों में जिले के सभी ब्लॉकों में भी लगाया जाएगा, ताकि सभी शासकीय महिला कर्मचारियों की जांच हो सके। उन्होंने कहा कि महिलाएं अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अक्सर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं। समय से पहले बीमारी का पता चलने पर उसका इलाज कराना आसान हो जाता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय ने 'प्रोजेक्ट सहारा' कार्यक्रम में जिला प्रशासन के नवाचारों की सराहना की थी। कलेक्टर ने सभी को स्वस्थ रहने और शासकीय कार्यों में बेहतर योगदान देने की शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई भी दी। नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की निःशुल्क जांच एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सराहनीय पहल है। जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन ने कहा कि शासकीय कर्मचारी हमेशा कार्य को प्राथमिकता देते हैं। इसी को देखते हुए 'प्रोजेक्ट छांव' के बाद अब "प्रोजेक्ट अभया" शुरू किया गया है। आने वाले समय में इसका विस्तार ब्लॉक स्तर तक किया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27